सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 280 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शुक्रवार 24 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त, सरकार ने लिखित में दिया भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लीक मामले में देशभर के युवाओं में उपजे आक्रोश और राजनीतिक दलों के लगातार प्रदर्शनों के बीच सरकार एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार सुबह से लेकर देर रात तक सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और कई घोषणाएं कीं। इसी घटनाक्रम के बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 26वें दिन देर रात लगभग 12:30 बजे अपना अनशन समाप्त कर दिया।

सोनम वांगचुक ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लद्दाख की एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। सांसदों और मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि नीट पेपर लीक और देश की परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी।

सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले दो दिनों से सरकार और उनके बीच बातचीत चल रही थी। वे सरकार से लिखित में आश्वासन चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें दो दिन अतिरिक्त अनशन पर बैठना पड़ा। आखिरकार, सरकार ने उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे दिया, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का निर्णय लिया। सोनम वांगचुक के अनुसार, सरकार ने लिखित में ये मांगें स्वीकार की हैं–

- **छात्रों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई:** जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले या 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में शामिल होने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।
- **पीड़ित परिवारों को मुआवजा:** पेपर लीक की घटना की वजह से जान गंवाने वाले 20 से अधिक बच्चों के परिवारों को सरकार उचित मुआवजा देगी।
- **संसद में होगी पूरी बहस:** देश की संसद में इस पूरे मुद्दे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जवाबदेही तय करने पर विस्तार से बहस और चर्चा होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर क्या बोले वांगचुक?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार इस बात का कोई आश्वासन नहीं दे सकी कि इस्तीफा कब होगा। उन्होंने बताया कि उनके पास दो रास्ते थे– या तो वे कई हफ्तों तक भूख हड़ताल जारी रखते जिससे उनकी जान जा सकती थी, या फिर अनशन समाप्त करते। उन्होंने कहा– पिछले 2–3 हफ्तों से हजारों लोग उनसे कह रहे थे कि संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उनका जीवित रहना जरूरी है।

खास-खबर

शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने गया युवक बहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर हिस्सों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। हालांकि इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश सामान्य श्रेणी में है, लेकिन यह औसत से 16त्न कम बनी हुई है। बारिश के बीच बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने गया 28 वर्षीय मछुआरा सुखदेव केवट तेज बहाव में बह गया।बिलासपुर, जांजगीर–चांपा और बलौदाबाजार पुलिस के साथ एसडीआरएफ ने देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज (शुक्रवार) फिर से सर्चिंग की जा रही है।

पूर्व सरपंच ने दूसरी पत्नी का चाकू से गला काटा, अफेयर के शक में हत्या, हुआ गिरफ्तार

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पति ने अफेयर के शक के चलते दूसरी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। पति ने पहले उसे शराब पिलाई, फिर सब्जी काटने वाले चाकू से गला काटकर धड़ से अलग कर दिया। शव को घर के पीछे फेंककर फरार हो गया था। महिला का शव करीब 6 दिनों तक घर के पीछे ही पड़ा रहा। जब शव सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए और पूरे इलाके में बदबू फैलने लगी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। आरोपी को गांव से ही हिरासत में लिया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आरोपी पति पूर्व सरपंच भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक, महिला झुमकी कुंजाम (35) अपने पति लक्ष्मण कुंजाम के साथ (36) के साथ दंतेवाड़ा जिले के गोंदपाल गांव में रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दंतेवाड़ा के कतियाररास में रह रहे थे।

महिला आरक्षक 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना में पदस्थ महिला आरक्षक तिलेश्वरी साहू को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। महिला आरक्षक पर कोर्ट के आदेश के बावजूद जब्त ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, सड़क दुर्घटना के एक मामले में कोड़ेनार पुलिस ने एक ट्रैक्टर जब्त किया था। बाद में न्यायालय ने ट्रैक्टर मालिक बंगालु यादव के पक्ष में सुपुर्दनामा जारी करते हुए वाहन सौंपने का आदेश दिया। आरोप है कि इसके बावजूद महिला आरक्षक तिलेश्वरी साहू ट्रैक्टर छोड़ने के लिए 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रही थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से की। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की।

सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के साथ ऐतिहासिक एमओयू

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर में डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप थे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन एवं आईआईटी मद्रास ब्वम्ै के बीच कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित दृष्टिकोण से कमी लाना है। कार्यशाला में अधिकारियों को बताया गया कि सड़क दुर्घटना डेटा का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जाएगी हाइपरलोकल सड़क सुरक्षा उपाय और कम लागत वाले अभियांत्रिकी हस्तक्षेप किए जाएंगे। 'संजय' प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लैक स्पॉट की समय पर पहचान कर साक्ष्य-आधारित निर्णय लिए जाएंगे।

प्रथम चरण में राज्य के सड़क दुर्घटना की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 10 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रत्येक सड़क दुर्घटना किसी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति होती है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि ऐसी सुरक्षित सड़क व्यवस्था विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। यह पहल सुरक्षित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने कहा कि संजय प्लेटफॉर्म से दुर्घटना संभावित स्थलों की वैज्ञानिक पहचान कर समयबद्ध हस्तक्षेप संभव होगा। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास कर दुर्घटनामुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का आह्वान किया।

कार्यशाला में चयनित 10 जिलों के कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, डीटीओ, एनआईसीसी के जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डेटा-आधारित योजना एवं त्वरित हस्तक्षेप से सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में प्रभावी कमी आएगी।

आवारा कुत्तों और मवेशियों के प्रबंधन पर हाईकोर्ट सख्तः कहा- राज्य सरकार करे निगरानी

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं, रेबीज के खतरे और राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर घूम रहे आवारा मवेशियों के प्रभावी प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के एसओपी पर उठाए गए कदम की मांगी जानकारी मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों के पालन में शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि आवारा पशुओं और कुत्तों के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर डिवीजन बेंच ने सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि मामला सीधे आम जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर दिया बयान, कहा–

दोषियों को कठोर दंड मिलेगा

नईदिल्ली(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के बढ़ते विरोध-प्रदर्शन के बीच गुरुवार सुबह नीट पेपर लीक को लेकर बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही। उन्होंने बताया कि मामले में संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी और हिंदी में लिखे पोस्ट में कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक को गंभीर पाप बताया था। प्रधानमंत्री मोदी का बयान ऐसे समय पर आया है, जब उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

एक दिन पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में यह घोषणा की है कि सरकार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक और उसके बाद शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

इसके बाद, संसद के मानसून सत्र के बीच विपक्षी सांसद भी लगातार संसद में सरकार को घेर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने से मुद्दा पूरे देश में छा गया है। सभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि सरकार ने अभी तक इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा है।

केयर इकोनॉमी विकसित छत्तीसगढ़ की आधारभूत आवश्यकता : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर में सुचारु एवं सशक्त केयर इकोनॉमी के निर्माण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, संचालक रणवीर शर्मा, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन रामजीवन देवांगन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, विकास सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि केयर इकोनॉमी केवल सामाजिक कल्याण नहीं, बल्कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारभूत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन, दिव्यांगजन, महिलाओं और बच्चों के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित एवं समावेशी व्यवस्था तैयार करना समय की आवश्यकता है। केयर सेक्टर में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, महिलाओं की कार्यभागीदारी सशक्त होती है और समाज अधिक संवेदनशील एवं समावेशी बनता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत /2047 के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन कल्याण, वृद्धजन सेवाओं, पुनर्वास, कौशल विकास तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित कर रही है। उन्होंने सभी विभागों से अभिसरण (कन्वर्जेंस) की भावना के साथ कार्य करते हुए मजबूत केयर इकोनॉमी के निर्माण का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने ष्नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशामुक्त समाज के निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं उनकी देखभाल का सामूहिक संकल्प लिया। सभी ने यह शपथ भी ली कि वे वृद्धजनों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, उनके सम्मान, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तथा समाज में सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के डॉ. ए.सी. रेड्डी ने विकसित भारत के निर्माण में केयर इकोनॉमी की केंद्रीय भूमिका पर व्याख्यान दिया। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस. ने केयर इकोनॉमी में रोजगार सृजन की संभावनाओं पर अपने विचार रखे।

संपादकीय

गहराता भूजल संकट

वर्षा जल के संग्रहण से करें पुनर्भरण

यह आंकड़ा डराने वाला है कि उत्तर भारत में भूजल का स्तर 450 घन किलोमीटर तक घट गया है। पिछले दो दशकों में आई यह गिरावट इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में खेती व जीवनयापन के लिए पानी की किल्लत हो सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में सिविल इंजीनियरिंग और पृथ्वी विज्ञान के 'विक्रम साराभाई चेयर प्रोफेसर' के एक अध्ययन में बताया गया है कि दो दशक में भूजल में आयी यह कमी भारत के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर बांध की कुल जल भंडारण मात्रा का 37 गुना है। दरअसल, भूजल में इस कमी की एक बड़ी वजह वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी बारिश में 8.5 फीसदी की कमी आना है। इस संकट का दूसरा पहलू यह भी है कि उत्तर भारत में सर्दियों के तापमान में 0.3 सेल्सियस वृद्धि देखी गई है। इस बात की पुष्टि हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के शोधार्थियों के एक दल ने की है। मानसून के दौरान कम बारिश होने और सर्दियों के दौरान तापमान बढ़ने के कारण आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से सिंचाई के लिये पानी की मांग में वृद्धि होगी। वहीं पानी की मांग बढ़ने से भूजल पुनर्भरण में भी कमी आएगी। जिसका दबाव पहले से ही भूजल के संकट से जूझ रहे उत्तर भारत के इलाके पर पड़ेगा। हैदराबाद स्थित एनजीआरआई का अध्ययन चेताता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जहां एक ओर मानसून के दौरान बारिश में कमी आएगी, वहीं सर्दियों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान रहने से भूजल पुनर्भरण में छह से 12 फीसदी तक की कमी आ सकती है। संकट का एक पहलू यह भी है कि हाल के वर्षों में मिट्टी में नमी में कमी देखी गई है। जिसका निष्कर्ष यह भी है कि आने वाले वर्षों में सिंचाई के लिये पानी की मांग में वृद्धि होगी। निश्चित ही यह स्थिति हमारी खेती और खाद्य श्रृंखला की सुरक्षा के लिये चिंताजनक कही जा सकती है।

> “ दरअसल, भूजल में इस कमी की एक बड़ी वजह वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी बारिश में 8.5 फीसदी की कमी आना है। इस संकट का दूसरा पहलू यह भी है कि उत्तर भारत में सर्दियों के तापमान में 0.3 सेल्सियस वृद्धि देखी गई है। इस बात की पुष्टि हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के शोधार्थियों के एक दल ने की है। मानसून के दौरान कम बारिश होने और सर्दियों के दौरान तापमान बढ़ने के कारण आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से सिंचाई के लिये पानी की मांग में वृद्धि होगी। वहीं पानी की मांग बढ़ने से भूजल पुनर्भरण में भी कमी आएगी। जिसका दबाव पहले से ही भूजल के संकट से जूझ रहे उत्तर भारत के इलाके पर पड़ेगा।

वहीं दूसरी ओर शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में पाया है कि मानसून के दौरान बारिश के प्रतिशत में गिरावट तथा सर्दियों में तुलनात्मक रूप से मौसम के गर्म होने से फसलों की सिंचाई के लिये अधिक भूजल की जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह यह भी है कि सर्दियों में तापमान अधिक होने से खेतों की मिट्टी तुलनात्मक रूप से शुष्क हो जाती है। यह कमी तभी पूरी हो सकती है जब हल्की बारिश की अवधि अधिक हो। देश के नीति-नियंताओं को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि भूजल के स्तर को कैसे ऊंचा रखा जा सके। जहां एक ओर वर्षा जल संग्रहण को ग्रामीण व शहरी इलाकों में युद्धस्तर पर शुरू करने की जरूरत है, वहीं अधिक पानी वाली फसलों के चक्र में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। इस संकट के आलोक में खेतिहर वर्ग को मुफ्त बिजली-पानी की राजनीति पर पुनर्विचार की जरूरत भी है। भूजल की सहज व सस्ती उपलब्धता उसके अधिक उपयोग को प्रेरित करती है। कृषि वैज्ञानिकों को ऐसी फसलों के लिये अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बावजूद अधिक तापमान व कम पानी में अधिक उपज दे सकें। सरकारों को यह नहीं भूलना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराना उनका प्राथमिक दायित्व है। खाद्यान्न के उत्पादन में कमी कालांतर महंगाई का कारण भी बनती है, जिससे जनाक्रोश में भी वृद्धि होगी। नीति-नियंताओं को गंभीरता से सोचना होगा कि पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए। यदि भूजल का यह संकट भविष्य में और गहराता है तो यह असंतोष का वाहक ही बनेगा। हमें बदलते मौसम के अनुकूल ही अपनी रीतियां-नीतियां बनानी होंगी। साथ ही पूरे देश में पानी के उपयोग के लिये अनुशासन की भी जरूरत होगी। अब चाहे हम नागरिक के रूप में हों, उद्योग व अन्य क्षेत्र में, पानी का किफायती उपयोग आने वाले भूजल संकट से हमारी रक्षा कर सकता है। यह एक गंभीर समस्या है और सरकार व समाज की सक्रिय भागीदारी इस चुनौती से मुकाबले के लिये जरूरी होगी।

सत्ता की सीढ़ी न बने बदलाव की आकांक्षाएं

क्षमा शर्मा

कोई भी आंदोलन किसी पुराने को उखाड़कर, नए को सत्ता सौंपने तक ही चलता है, बाद में विलीन हो जाता है। चूंकि सत्ता अपने तंत्र और निरंकुशता से ही चलती है, बस चेहरे बदलते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि तमाम क्रांतिकारी और आकर्षक नारे किसी को सत्ता से हटाने और किसी को सत्ता सौंपने का उपक्रम भर होते हैं।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में भाग लेने वाले सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत की खबरें आ रही थीं। बताया गया कि आमरण अनशन के कारण उनका वजन लगातार कम हो रहा था। हाईकोर्ट ने भी कहा कि उनकी सेहत की चिंता की जाए। ऐसे में यदि उन्हें पुलिस ने अस्पताल में दाखिल कराया, तो क्या गलत किया? अगर उनकी जान चली जाती, तो क्या होता? इस आंदोलन में छात्रों से संबंधित जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि पेपर पर पेपर लीक होते जाते हैं? लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।

हमने सबसे पहले इस तरह का आंदोलन सत्तर के दशक में देखा था। आपातकाल के बाद सरकार की नीतियों के खिलाफ स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था, कहते हैं कि इसीलिए उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं। उस समय न सोशल मीडिया था, न रात-दिन चलते इतने चैनल्स, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया, उसमें लोगों ने जमकर भागीदारी की। तमाम विपक्षी दल, एक-दूसरे के घोर विरोधी वाम और दक्षिणपंथी विचार, सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इंदिरा गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। इसे दूसरी आजादी और संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने कोई पद भी नहीं लिया। वे इंदिरा गांधी से मिलने भी गए। जब इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि अब वे क्या करें, तो जे.पी. ने कहा कि फिर से लोगों के बीच जाओ।

लेकिन जैसे ही कोई जीतता है, तमाम हित आपस में टकराने लगते हैं। उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह में काफी खींचतान चली। जितना बहुमत मिला था, उसे जैसे सभी विपक्षी दलों की सात भात की खिचड़ी चला ही नहीं सकी। उधर जे.पी. की सलाह मानकर इंदिरा गांधी खूब सक्रिय हो गईं। नतीजा यह हुआ कि 1977 की जनता पार्टी की जीत 1980 आते-आते कांग्रेस की जीत में बदल गई। दूसरी आजादी और संपूर्ण क्रांति का सपना धराशायी हो गया।

इसके बाद कांग्रेस के ही नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनका कहना था कि राजीव गांधी ने बोफोर्स सौदे में दलाली खाई है। हालांकि कहीं कोई प्रमाण न मिला, लेकिन एक बार किसी नेता की छवि पर दाग लग जाए, तो लोग उसे सच मान लेते हैं। इसलिए राजीव गांधी चुनाव हार गए। उनकी सुरक्षा तक वापस ले ली गई, जबकि वे आतंकवादियों की हिट लिस्ट में थे। और उनका अंत भी वही हुआ जो इंदिरा गांधी का हुआ था। चेन्नई में एक सभा के दौरान लिट्टे आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीलंका में भारतीय सेना लिट्टे से निपटने के लिए भेजी थी। इंदिरा गांधी खालिस्तानियों के हाथों शहीद हुईं, तो राजीव गांधी लिट्टे के हाथों। कहा जाता है कि राजनीति को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है।

फिर इस सदी के दूसरे दशक यानी कि 2011 में लोगों ने अन्ना आंदोलन को देखा। इसे मूलतः लोकपाल के लिए किया गया था, जिससे कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। इस आंदोलन ने भी अभूतपूर्व सफलता पाई। लोगों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। ऐसी खबरें भी आईं कि बहुत से युवा विदेशों से अपनी अच्छी-खासी नौकरियां छोड़कर इसमें भाग लेने आए। अन्ना ने इस आंदोलन को शुरू जरूर किया था, लेकिन इसमें भाग लेने वाले भूतपूर्व आई.आर.एस. अधिकारी अरविंद केजरीवाल नेता बनकर उभरे। उन्होंने उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ भी खूब अभियान चलाया। ऑटो के पीछे तक एक शीला दीक्षित और एक अरविंद केजरीवाल के फोटो लगे रहते थे। शीला दीक्षित के फोटो के नीचे लिखा रहता था— 'बेईमान' और अरविंद केजरीवाल के फोटो के नीचे— 'ईमानदार'। नतीजा वही हो सकता था, शीला दीक्षित चुनाव हार गईं और अरविंद केजरीवाल जीत गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हालांकि सरकार उन्हें उसी कांग्रेस के समर्थन से बनानी पड़ी, जिसका वे विरोध करते आए थे।

यानी कि कोई भी आंदोलन किसी पुराने को उखाड़कर, नए को सत्ता सौंपने तक ही चलता है, बाद में विलीन हो जाता है। चूंकि सत्ता अपने तंत्र और निरंकुशता से ही चलती है, बस चेहरे बदलते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि तमाम क्रांतिकारी और आकर्षक नारे किसी को सत्ता से हटाने और किसी को सत्ता सौंपने का उपक्रम भर होते हैं। जो लाखों लोग बदलाव का सपना लिए इनमें भाग लेते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। उनके हाथ सिर्फ पछतावा आता है कि जिस बदलाव का सपना देखा था, वह बस सपना ही रह गया। कम से कम अतीत के सबक तो यही हैं।

अब कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर-मंतर पर जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें। वे सत्ता से सवाल पूछें। जवाब न मिले, तो इसे उखाड़ फेंकें। जेन-जी नेपाल, श्रीलंका या अरब स्प्रिंग की तरह इसमें बढ़-चढ़कर भाग ले। अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपिके ने भारत आकर इसे शुरू किया, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक इसमें भाग लेने आए, मीडिया की सारी लाइमलाइट उन्हें मिलने लगी। दीपिके कहीं पीछे छूट गए। अब जब वांगचुक अस्पताल में हैं, तो उनकी पत्नी गीतांजलि ने घोषणा कर दी है कि वे इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगी। इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है? ये सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि हर शहर में जंतर-मंतर जैसा आंदोलन स्थल बना लिया जाए, वहां आकर बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन से जुड़ें। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से कहा कि बीस जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन है। देखना है कि वे अपने मकसद में कितना सफल होते हैं।

चूंकि इस लेखिका ने अतीत में कम से कम तीन बड़े आंदोलन देखे हैं, वे जिन प्रतिज्ञाओं से शुरू किए गए थे, सत्ता मिलते ही भुला दी गईं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी लोगों ने बढ़-चढ़कर दूसरी आजादी कहा था, अब सोनम वांगचुक भी यही कह रहे हैं। लेकिन यह समय भी सत्तर का दशक नहीं है। इक्कीसवीं सदी को भी शुरू हुए पच्चीस साल बीत गए हैं। मुख्यधारा का मीडिया जिसे कहा जाता है, उसके मुकाबले सोशल मीडिया पल-पल की खबर दे रहा है। अब चालाकी से किसी चीज को छिपा लेना भी मुश्किल है। यही नहीं, पहले तो लोग अपने ही कहे को नकार देते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो बताया जा रहा है, अब तो जैसे ही कोई अतीत में कही बात को नकारता है, फौरन वीडियो या रील प्रस्तुत कर दी जाती है। इसलिए नेतागिरी चमकाना आसान है, वास्तविक नेता बनना कठिन।

लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मुकाबलों की संख्या कम होने से घटा उत्साह

हरजीत सिंह

भारतीय दल की संख्या कम होने की वजह इस बार के खेलों में कम स्पर्धाओं का होना माना जा सकता है। इस बार मुख्य खेलों में सिर्फ़ दस को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की भागीदारी मुख्यतः एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में होगी। ओलंपिक की तर्ज़ पर आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आज से हो रही है। कुल 70 से अधिक देशों की भागीदारी वाले इस आयोजन को ओलंपिक के बाद दूसरा बड़ा खेल-मेला माना जाता है। ब्रिटिश सल्तनत के अंतर्गत आने वाले देशों के बीच खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 1930 में इनकी शुरुआत हुई थी। तब इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। भारत ने अपनी पहली उपस्थिति 1934 में दर्ज की थी।

23 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चार बार— 1930, 1950, 1962 और 1986— को छोड़कर सभी खेलों में भाग लेता रहा है। वर्ष 1934 में अपनी शुरुआत के बाद से भारत ने अब तक 564 पदक जीते हैं, जिनमें 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य शामिल हैं। पदक तालिका में शामिल देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। पहलवान राशिद अनवर 1934 के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। पिस्टल निशानेबाज जसपाल राणा राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट रहे, जिन्होंने 1994 से 2006 तक के चार खेलों में नौ स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य सहित 15 पदक जीते।

भारत ने 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में किया था। इस आयोजन में भारत ने दूसरे स्थान के साथ 101 पदक जीते थे, जो कि भारत का इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उसके बाद के तीन राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, जहां भारत पांचवें, तीसरे और चौथे स्थान पर रहा। लेकिन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल में कुछ उदासीनता है। वजह बड़ी गंभीर भी है। इस बार भारतीय दल की संख्या मात्र 126 है, जो कि पिछले दो मुकाबलों— 2018 में 221 और 2022 में 215— से काफी कम है। भारतीय दल की संख्या कम होने की वजह इस बार के खेलों में कम स्पर्धाओं का होना माना जा सकता है। इस बार मुख्य खेलों में सिर्फ दस को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की भागीदारी मुख्यतः एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में होगी।

भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग में 63 स्वर्ण के साथ कुल 135

पदक जीते हैं, जो इस बार राष्ट्रमंडल खेलों से नदारद है। 2022 खेलों में भारत ने कुश्ती, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन ये खेल भी इस बार शामिल नहीं हैं। इसके अलावा भारोत्तोलन भी भारत के लिए एक सिरदर्द है, जहां 16 खिलाड़ियों के कोटा होने के बावजूद सिर्फ़ 12 ही जा पा रहे हैं। वजह कई खिलाड़ियों का डोपिंग में लिप्त होना है।

इस बार खेलों में कमी की एक बड़ी वजह ग्लासगो को इसकी मेजबानी का देर से मिलना था। 23वें राष्ट्रमंडल खेल पहले ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया को दिए गए थे, पर 2023 में विक्टोरियन राज्य सरकार ने बढ़ती लागत के अनुमानों के कारण अपनी योजनाओं को रद्द कर दिया। 17 सितंबर, 2024 को स्कॉटिश सरकार ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय सहायता के साथ सहमति बनाई। कम समय की वजह से ग्लासगो 2026 खेलों में लागत को नियंत्रित करने के लिए केवल 10 खेलों के साथ एक कॉम्पैक्ट प्रारूप तैयार हुआ, जिसमें एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, तैराकी और पैरा तैराकी, कलात्मक जिमनास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन और पैरा पावरलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो, लॉन बाउल्स और पैरा लॉन बाउल्स, बास्केटबॉल और व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल हैं। इसमें कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन और निशानेबाजी जैसे भारत के कुछ पारंपरिक वर्चस्व वाले खेल शामिल नहीं हैं। इसके बावजूद, भारत हाल की सफलताओं के आधार पर एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन जैसे क्षेत्रों में मजबूती से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है।

भारत की नज़र इस बार एथलेटिक्स पर रहेगी। 28 वर्षीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 32 खिलाड़ियों (जिसमें 10 महिलाएं हैं) की टीम का नेतृत्व करेंगे। वर्ष 2018 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने 2022 खेलों में कमर की चोट की वजह से भाग नहीं लिया था। उनके अलावा ट्रिपल जम्पर सेल्वा प्रभु, 5000 मीटर की धाविका पारुल चौधरी, लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह, शॉटपुटर मनप्रीत कौर और तेजिंदरपाल सिंह तूर तथा लॉन्ग जम्पर लोकेश सत्यनाथन से उम्मीद की जा सकती है।

दो बार राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मीराबाई चानू भारोत्तोलन टीम का मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ देने के लिए 58 किलोग्राम श्रेणी में बिंदियारानी देवी और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर हैं। पुरुष वर्ग में ऋषि सिंह, एम. राजा, अजय बाबू, दिलबाग सिंह और लवप्रीत सिंह अपना दमखम दिखाएंगे। भारतीय बॉक्सिंग का भार भी ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर रहेगा। कुल मिलाकर 12 मुक्केबाज ग्लासगो जा रहे हैं। भारत ने ग्लासगो 2026 के लिए छह सदस्यीय लॉन बाउल्स टीम का भी चयन किया है। रूपा रानी तिर्की और नयनमोनी सैकिया लॉन बाउल्स में भारत के लिए पहला राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं।

ग्लासगो में बेशक सभी भारतीय खिलाड़ी अपने खेल-कौशल का प्रदर्शन न कर पाएं, पर 2030 में अहमदाबाद को शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान के रूप में अनुमोदित करने के बाद भारत को हॉकी और कुश्ती जैसे नज़रअंदाज किए गए खेलों को फिर से शुरू करने का मौका रहेगा।

संकटग्रस्त क्षेत्रों के जोखिम में भारतीय नाविक

पुष्परंजन

भारत सरकार ने पश्चिम एशिया और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाविक-प्रथम अभियान शुरू किया है। इसके तहत नाविकों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, संपर्क अधिकारी की नियुक्ति और चौबीसों घंटे आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी।

इस साल संघर्ष वाले इलाकों में कमर्शियल जहाजों पर काम करते हुए 15 से ज़्यादा भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। जुलाई, 2026 तक हुई ये मौतें अमेरिका-ईरान संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान हुईं, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि रूसी चार्ज द अफेयर्स व्लादिमीर लादानोव को तलब किया गया और मंत्रालय ने उन्हें '19 जुलाई 2026 को कमर्शियल जहाज़ एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं से कड़ी निंदा के साथ अवगत कराया, जिसमें चार भारतीयों की दुखद मौत हो गई थी।'

क्रेमलिन का कहना है कि चार नाविकों की मौत पर भारत के विरोध के बावजूद, यूक्रेन के लिए हथियार ले जाने वाले जहाज उसके निशाने पर बने रहेंगे। यह अपने आप में विचित्र है कि जो क्रेमलिन इस तरह के बयान दे रहा है, वह भूल जाता है कि रूस की तरफ से लड़ने वाले भारतीय भी बड़ी संख्या में मरे हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि रूसी सेना में सेवा के दौरान 49 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। छह भारतीय नागरिक लापता हैं।

20 से 24 जुलाई, 2026 को मनीला में आहूत आसियान बैठक में इस तल्खी को कम करने के वास्ते विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा

की। ब्लैक सी में हुए मिसाइल हमले में चार भारतीय नाविकों की मौत के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली उच्चस्तरीय बैठक थी। बातचीत में भारतीय नाविकों की सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसे मानना पड़ेगा कि भारतीय नाविकों पर खतरा ज़्यादा है, क्योंकि भारत दुनिया में समुद्री कर्मचारियों (सीफेयरर्स) का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। समुद्री कर्मचारियों की आपूर्ति में फिलीपींस दुनिया में सबसे आगे है, जो पांच लाख से ज़्यादा क्रू सदस्यों की आपूर्ति करता है। चीन और भारत क्रमशः दूसरे-तीसरे नंबर पर हैं। दुनिया भर में तीन लाख से ज़्यादा भारतीय नाविक काम करते हैं। वे अक्सर ऐसे कमर्शियल जहाज़ों पर काम करते हैं, जिन पर दूसरे देशों का झंडा लगा होता है और जो लड़ाई-झगड़े वाले इलाकों (कॉन्फ़्लिक्ट ज़ोन) से गुज़रते हैं। इस वजह से ये नाविक अक्सर अंतरराष्ट्रीय सैन्य हमलों में अनजाने में मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं।

काला सागर की घटना हाल की है, जब यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से निकलते समय कार्गो जहाज़ एमवी गोल्डन लियो पर रूसी क्रूज़ मिसाइल हमले में चार भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जब कमर्शियल तेल टैंकरों पर हमला हुआ, कई भारतीय नाविकों की जान चली गई। क्योंकि भारतीय नाविक ग्लोबल मर्चेंट नेवी का एक बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए जब-तब लड़ाई की चपेट में आते हैं।

ज़्यादातर भारतीय नाविक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करते हैं। वे विदेशी रजिस्ट्रेशन वाले जहाज़ों पर काम करते हैं, चुनांचे नुकसान पहुंचने पर राजनयिक प्रतिक्रिया देना भारत के लिए मुश्किल हो जाता है। भले ही भारत के समुद्री रेगुलेटर ने कंपनियों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे रास्तों पर भारतीय नागरिकों को तैनात न करने की सलाह दी है, फिर भी कई जहाज़ मुनाफ़े के लिए यह जोखिम भरा सफर करते हैं। यह दीगर है कि दुनिया के अहम व्यापारिक मार्ग इन ख़तरनाक समुद्री इलाकों से गुज़रते हैं।

विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हुए मरने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों को शव को वापस लाने, जांच और मुआवज़े की प्रक्रिया शुरू करना आसान नहीं होता। इसके लिए विदेश मंत्रालय या निकटतम भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से संपर्क ही शुरुआती रास्ता है। विदेशों में स्थित भारतीय मिशन मृत्यु की पुष्टि करते हैं, ज़रूरी यात्रा, पारगमन दस्तावेज़ जारी करते हैं और शव या अस्थियों को वापस लाने की प्रक्रिया की देखरेख करते हैं। शिपिंग कंपनियों के लिए यह कानूनी रूप से ज़रूरी है कि वे काम से जुड़ी चोट, बीमारी या खतरे के कारण मृत्यु या दीर्घकालिक विकलांगता के लिए मुआवज़े को कवर करने वाला वैध बीमा रखें।

लेकिन जो अवैध जहाज है, वहां काम करने वाले भारतीयों का क्या होता होगा? अवैध या ब्लैकलिस्टेड जहाजों (शैडो फ्लीट) में काम करने वाले भारतीयों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर बिना वेतन के महीनों तक समुद्र में छोड़ दिया जाता है और खतरनाक संघर्ष क्षेत्रों में हमलों का भारी जोखिम रहता है। वे यदि हमलों में मारे जाते हैं, उनका कोई माई-बाप नहीं होता।

जून, 2026 की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हवाई हमले में टैंकर सेटेबेलो के इंजन रूम को निशाना बनाए जाने से तीन भारतीय मर्चेंट नाविक मारे गए। यह जहाज शैडो फ्लीट टैंकरों के उस नेटवर्क का हिस्सा था, जिनका इस्तेमाल अपनी पहचान छिपाने और प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले ईरानी तेल की ढुलाई के लिए किया जाता था। अमेरिकी सेना ने बताया कि ईरानी तेल की खेप पर अमेरिकी नाकेबंदी को मानने की चेतावनियों को बार-बार नज़रअंदाज़ करने के बाद इस जहाज को निशाना बनाया गया। मतलब, जो भारतीय उस जहाज पर थे, उनकी मौत की ज़िम्मेदारी लेने से अमेरिकी नौ सेना ने पल्ला झाड़ लिया।

जुलाई, 2026 में भी ऐसा ही हुआ। ओमान के तट पर तीन दिनों में तीन टैंकरों पर तीन हमले हुए, जिनमें तीन लोगों की मौत हो गई। उन हमलों में 65 भारतीय नाविकों को बचाने की ज़रूरत आन पड़ी। इन तीन हमलों ने नई दिल्ली में 'शैडो फ्लीट' (यानी ग्रे एरिया में काम करने वाले जहाज़ों) पर मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। गत 14 जुलाई, 2026 को जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बयान दिया कि भारत सरकार ने पश्चिम एशिया और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाविक-प्रथम अभियान शुरू किया है। इसके तहत नाविकों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, संपर्क अधिकारी की नियुक्ति और चौबीसों घंटे आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी।

'शैडो फ्लीट' (अवैध बेड़े) के तेल पर भारत की भारी निर्भरता की अमेरिका और अन्य पश्चिमी सहयोगियों ने कड़ी आलोचना की है। शुक्र मनाइये कि जिन शैडो फ्लीट से अभी तक जो सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, उसमें भारत सरकार एक्सपोज़ नहीं हुई है। लेकिन, कोई बड़ा हादसा इसका इंतज़ार कर रहा है। क्या सरकार को इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि जो भी भारतीय दुनिया भर में कमर्शियल जहाजों पर काम कर रहे हैं, उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो और उनकी मॉनिटरिंग समय-समय पर हो!

लेखक जियो-पॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

बीएसपी की माइन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कार्यशाला का शुभारंभ

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के सीजी ग्रूप ऑफ माइंस के लिए आयोजित पाँच दिवसीय माइन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान-इम्प्लीमेंटेशन एवं रिव्यू प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का शुभारंभ 21 जुलाई 2026 को राजहरा स्थित माइन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य खदानों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित एवं उत्तरदायी कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करना है। उद्घाटन सत्र में कार्यपालक निदेशक कमल भास्कर तथा मुख्य महाप्रबंधक आर. बी. गहरवार उपस्थित रहे। कार्यशाला के अगले चरण में 23 से 25 जुलाई 2026 तक दल्ली मैकेनाइज्ड माइंस, राजहरा मैकेनाइज्ड माइंस एवं नंदिनी चूना पत्थर खदान में स्थल-आधारित हैंडहोल्डिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों के दौरान प्रत्येक खदान के वर्तमान माइन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा की जाएगी, कमियों की पहचान कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव दिए जाएंगे।

रूफटॉप सोलर प्लांट ने संतोष मेहता को बनाया ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर

दुर्ग। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम बनकर सामने आई है। दुर्ग शहर के गिरधारी नगर, वार्ड क्रमांक 9 की निवासी संतोष मेहता इस योजना का लाभ लेकर न केवल अपने परिवार का बिजली खर्च लगभग समाप्त करने में सफल हुए हैं, बल्कि अब अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर आर्थिक लाभ की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले तक उनके परिवार को हर माह बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने से बिल भी अधिक आता था, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होता था। अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कराया। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 78,000 तथा छत्तीसगढ़ शासन से 30,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई। कुल 1.08 लाख की सरकारी सहायता मिलने से सोलर प्लांट की स्थापना आसान और किफायती हो गई।

पावस ऋतु पर सरस काव्य गोष्ठी 26 जुलाई को

भिलाई। 'साहित्य सृजन परिषद्' के तत्वावधान में पावस ऋतु पर सरस काव्य गोष्ठी रविवार 26 जुलाई को इंदिरा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुपेला-भिलाई में अपराह्न 2:30 बजे से आयोजित की गई है। परिषद के अध्यक्ष एनएल मौर्य 'प्रीतम' ने बताया कि गोष्ठी में मुख्य अतिथि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ हंसा शुक्ला होंगी। अध्यक्षता प्रख्यात संस्कृत विद्वान आचार्य डॉ महेशचंद्र शर्मा करेंगे। विशिष्ट अतिथि इंदिरा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक काशीनाथ वर्मा, प्रगतिशील जन-विचारधारा की साहित्यिक संस्था 'आरंभ' के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य और समाजसेवी घनश्याम कुमार देवांगन होंगे।

अमर शहीद कौशल यादव के शहादत दिवस पर 25 जुलाई को हुडको स्मारक स्थल पर होगा समारोह

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। कारगिल योद्धा अमर शहीद वीर चक्र सम्मानित कौशल यादव के 27वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ आर्मी वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा 25 जुलाई सुबह 11 बजे हुडको स्थित कौशल यादव स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा व स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में गुरूवार को छत्तीसगढ़ आर्मी वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता के माध्यम से जानकारी दी।

संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हरप्रीत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में कारगिल योद्धा अमर शहीद वीर चक्र सम्मानित कौशल यादव के 27वें शहीद दिवस के अवसर पर दिनांक 25 जुलाई को एक भव्य श्रद्धांजलि एवं स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर शहीद कौशल यादव के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

यह कार्यक्रम नई पीढ़ी में देशभक्ति, राष्ट्रसेवा एवं सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का एक विनम्र प्रयास है। स्मृति दिवस समारोह के दौरान रक्त दान शिविर व स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, मीडिया प्रतिनिधियों लथा समस्त नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अमर शहीद कौशल यादव को श्रद्धासुमन अर्पित करें तथा उनके सर्वोच्च बलिदान को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दें। प्रेस वार्ता के दौरान हरप्रित सिंग (पूर्व सैनिक एडवेंचर), कैप्टन ओपी सिंह, मनीष शर्मा, वीके सिंह, बेनी प्रसाद, शैलेन्द्र कुमार, नेहा मोदी आदि उपस्थित रहे।

विधायक रिकेश सेन की एक और बड़ी घोषणा

पीएम आवास के हितग्राहियों को बेटी की शादी पर मिलेगा निःशुल्क गैस कनेक्शन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जनहित और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखकर लगातार नवाचारपूर्ण योजनाएं लागू कर रहे विधायक रिकेश सेन ने आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवारों में बेटियों का विवाह होने पर नवविवाहित दंपत्ति को नि:शुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा प्रदान किया जाएगा। इस नई पहल का शुभारंभ 10 अगस्त से किया जाएगा।

विधायक रिकेश सेन का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटी के विवाह के बाद नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत सुविधाजनक और सम्मानजनक हो, यही इस योजना का उद्देश्य है। उनका मानना है कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन स्तर से भी जुड़ा हुआ है।

गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा में पिछले कुछ समय से विधायक रिकेश सेन लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। मात्र एक रुपये में चश्मा उपलब्ध कराने की योजना के माध्यम से हजारों लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मां-शिशु सुरक्षा कवच योजना के तहत नवजात शिशुओं और माताओं को आवश्यक सामग्री से युक्त सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और जरूरतमंद परिवारों की सहायता को लेकर विधानसभा क्षेत्र में लगातार नई पहल की जा रही हैं, जिन्हें व्यापक जनसमर्थन भी मिल रहा है।

आपको बता दें कि विधायक रिकेश सेन केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी पहलें सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ती दिखाई देती हैं।

स्थानीय नागरिकों ने भी इस नई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि बिटिया के विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे नए परिवारों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक रसोई की शुरुआत करने में मदद मिलेगी।

लगातार जनहित, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से वैशाली नगर विधानसभा में विकास की नई कार्यशैली देखने को मिल रही है। विधायक रिकेश सेन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाना है। इसी सोच के साथ 10 अगस्त से शुरू होने वाली यह नई योजना भी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात साबित होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त आवेदनों की निकाय स्तरीय समिति ने की पात्रता की जांच

भिलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान-मोर आस घटक अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में झुग्गी बस्ती एवं गैर स्लम क्षेत्रों में किरायेदार के रूप में निवासरत परिवारों से आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लगातार आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। योजना के तहत परिवारों द्वारा वर्तमान में कुल 348 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता संबंधी जांच एवं दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान 340 आवेदन पूर्ण एवं पात्र पाए गए, जबकि आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में 08 आवेदन अपूर्ण पाए गए हैं। पूर्ण एवं अपूर्ण दस्तावेजों सहित जमा किए गए समस्त आवेदन पत्रों को पात्रता की जांच एवं परीक्षण के लिए निकाय स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। गुरूवार को नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार कक्ष में निकाय स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान-मोर आस घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का बारीकी से परीक्षण किया गया। समिति द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पात्रता संबंधी आवश्यक मापदंडों का अवलोकन करते हुए आवेदन पत्रों की जांच की गई। बेघर परिवारों को लगातार आवास हेतु आवेदन वितरण किया जा रहा है, जिसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा भी कराया जा रहा है। नगर निगम के आवास शाखा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर लाटरी के माध्यम से आवास आबंटन की कार्यवाही किया जा रहा है।

दस्तावेज परीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी दिनेश कोसरिया, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी, उप अभियंता दीपक देवांगन, आवास प्रभारी विदयाधर देवांगन, नम्रता ठाकुर उपस्थित रहे।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा गोढ़ी एवं खोपली गांवों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करने की दिशा में दुर्ग जिला चिकित्सालय के सहयोग से दुर्ग जिले के गोढ़ी एवं खोपली गांवों में नि:शुल्क चिकित्सा जांच एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविरों का आयोजन किया। शिविरों में ग्रामीणों को नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श तथा आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।

दिनांक 20 जुलाई 2026 को दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड स्थित ग्राम गोढ़ी में आयोजित चिकित्सा शिविर में जिला चिकित्सालय, दुर्ग की ओर से चिकित्सा अधिकारी डॉ. गायत्री श्याम, फार्मासिस्ट जान्हवी, नर्सिंग स्टाफ तृप्ति कुमारी, पंजीयन सहयोगी राकेश कुमार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) गुलेश्वरी साहू ने सेवाएं प्रदान कीं। शिविर में कुल 40 ग्रामीणों, जिनमें 12 पुरुष एवं 28 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं नि:शुल्क दवाइयां प्रदान की गईं।

इसी क्रम में 21 जुलाई 2026 को दुर्ग जिले के निकुम विकासखंड स्थित ग्राम खोपली में आयोजित चिकित्सा शिविर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. गायत्री श्याम, फार्मासिस्ट मनीष देशमुख, नर्सिंग स्टाफ रेणुका वर्मा तथा पंजीयन सहयोगी विवेक ध्रुव ने अपनी सेवाएं दीं। इस शिविर में 50 ग्रामीणों, जिनमें 28 पुरुष एवं 22 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं नि:शुल्क दवाइयां वितरित की गईं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित इन चिकित्सा शिविरों का सफल संचालन जिला चिकित्सालय, दुर्ग के सक्रिय सहयोग से किया गया।

महापौर अलका बाघमार ने नाली निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत महापौर अलका बाघमार ने वार्ड क्रमांक 23 दीपक नगर, मालवीय नगर तथा वार्ड क्रमांक 16 सिकोला भाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन नाली कार्यों का स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता, तकनीकी मानकों एवं जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लोक कर्म विभाग के प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, एमआईसी सदस्य निलेश अग्रवाल, पार्षद मनोज सोनी, उप अभियंता पंकज साहू, सिद्धार्थ साहू, उप अभियंता अपर्णा मिश्रा सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी नाली निर्माण कार्य स्वीकृत डीपीआर, स्वीकृत ड्राइंग एवं निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप ही किए जाएं। उन्होंने कहा कि नालियों में निर्धारित डिज़ाइन के अनुसार पर्याप्त एवं समान ढाल (ग्रेडिएंट) सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षा एवं अपशिष्ट जल का निर्बाध प्रवाह बना रहे और कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

महापौर ने कहा कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रारंभिक एवं अंतिम लेवल का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। निर्माण में उपयोग होने वाली सीमेंट, गिट्टी, रेत सहित सभी सामग्री निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप हो तथा नाली के जॉइंट्स, फिनिशिंग एवं सतह को मजबूत एवं समतल बनाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क, पेयजल पाइपलाइन, विद्युत पोल एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे तथा निकलने वाले मलबे का नियमित निष्पादन कर आवागमन सुचारु बनाए रखा जाए।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि कार्य पूर्ण होने के बाद नाली में पानी प्रवाहित कर वॉटर फ्लो टेस्ट कराया जाए। परीक्षण में ढाल एवं जल निकासी संतोषजनक पाए जाने के बाद ही संबंधित कार्य का देयक तैयार किया जाए।

ई-ऑफिस से लेकर सड़क, स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास और जल संरक्षण तक कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने आयुक्त ने दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने गुरुवार को निगम के विभिन्न विकास, निर्माण, सौंदर्यीकरण एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निगम मुख्य कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने बैठक में निगम के कार्यों को गति देने के साथ-साथ नागरिकों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी कार्य निर्धारित समय.सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में आयुक्त ने सबसे पहले निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को प्राथमिकता से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शत प्रतिशत नस्तियों को डिजिटल सिग्नेचर के साथ ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, ताकि शासकीय कार्यों में तेजी आए और फाइलों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो। आयुक्त ने सभी जोन आयुक्त एवं संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिदिन भ्रमण कर जमीनी स्थिति का जायजा लेने तथा क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं और कमियों की तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान कार्यालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि मौके पर पहुंचकर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने तथा शिकायतों के लंबित रहने की स्थिति को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए गए।

आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की उपस्थिति में नंदिनी रोड से अवंति बाई चौक तक लगभग 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये। इसके साथ ही मुख्य मार्गों की सड़कों पर हुए गड्ढों को तत्काल भरने और आवश्यक सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मकानविहीन परिवारों को योजना का लाभ समय पर दिलाने के लिए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ जल्द से जल्द मिलना चाहिए और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर आयुक्त ने अधिकारियों को प्रमुख मार्गों पर बंद स्ट्रीट लाइटों का तत्काल संधारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एलईडी लाइट की सप्लाई एवं रिपेयरिंग का कार्य व्यवस्थित रूप से कराने तथा प्रमुख चौक-चौराहों पर हाईमास्ट लाइट लगाने की दिशा में कार्यवाही करने को कहा, जिससे रात्रि के समय शहर में अंधेरा समाप्त हो और नागरिकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है - किरण देव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए छात्रों का हित सबसे महत्वपूर्ण है और वे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले रहे हैं। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री देव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में गुरुवार को आहूत पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के इस आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं की घुसपैठ करा कर छात्रों के आंदोलन का स्वरूप ही बदल दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस विषय को पहले दिन से ही गंभीरता से लेकर यह निर्णय किया है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है व उनके नुकसान की भरपाई भी होगी। श्री देव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भाषण हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में होता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेसी नेताओं ने भाषणों में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। यह लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। प्रजातंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है।

मैदानी जिलों में झमाझम, बस्तर में बारिश की रफ्तार धीमी

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 23 जुलाई 2026 तक जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक औसतन 403.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि बीते 10 वर्षों के औसत (436.3 मिमी) का लगभग 92.5 प्रतिशत है। प्रदेश भर में हुई इस 15.2 मिमी की दैनिक बारिश से राज्य के बड़े हिस्से में खेती-किसानी के कार्यों में तेजी आ गई है। आंकड़ों के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला बारिश के मामले में सबसे आगे चल रहा है, जहां सामान्य औसत से 186.9त्न अधिक (639 मिमी) बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसी तरह बलरामपुर में 158.4प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 127.5 प्रतिशत, सक्ती में 123.8 प्रतिशत, और प्रदेश की राजधानी रायपुर में 123.1त्न बारिश हो चुकी है। बिलासपुर (117 प्रतिशत), मुंगेली (116 प्रतिशत), दुर्ग (113.5 प्रति.), बलौदाबाजार (121त्न) और महासमुंद (114.3त्न) जैसे जिलों में भी मेघ जमकर बरसे हैं, जिससे स्थानीय जलनिकाय लबालब भरने लगे हैं।

बीजापुर में तेजस स्टार्टअप वर्कशॉप का शुभारंभ

बीजापुर। जिला प्रशासन एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीजापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तेजस स्टार्टअप वर्कशॉप का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पेरे पुलैय्या तथा कलेक्टर विश्वदीप की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जिले के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता और स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहित कर उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर कलेक्टर विश्वदीप ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप केवल नया व्यवसाय शुरू करने का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं का नवाचारी समाधान विकसित करने का प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि बीजापुर जैसे जिले में कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

आदिवासी ज्ञान और व्यवहार विज्ञान से संवरेगा किशोरों का भविष्य, 'मूल मंथन' में छत्तीसगढ़ मॉडल पर विमर्श

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश के आदिवासी अंचलों के बच्चों और किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षित भविष्य के लिए समुदाय, संस्कृति और व्यवहार विज्ञान पर आधारित योजनाएं तैयार की जाएंगी। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आज राजधानी रायपुर में 'मूल मंथन आदिवासी ज्ञान से किशोरावस्था की पुनर्कल्पना' विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला के पहले दिन विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति जताई कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा बनाए रखते हुए सामुदायिक नेतृत्व को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर ही स्थायी परिवर्तन संभव है।

शुभारंभ सत्र में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि जनजातीय समुदायों के साथ सम्मान, संवेदनशीलता और विश्वास के आधार पर जुड़ना ही किसी भी प्रभावी नीति की सफलता का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि योजनाएं तभी सफल होंगी, जब उनका निर्माण समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर किया जाएगा।

आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर सहित जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है। उन्होंने स्थानीय भाषाओं को व्यवहार परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि विकास का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति को बदलना नहीं, बल्कि उसकी अंतर्निहित शक्ति को पहचानकर उसे समाज के हित में उपयोग करना है।

उन्होंने प्रदेश के जनजातियों को विकास की मूलधारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय इस मूलमंथन में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी रिपोर्ट के आधार पर जनजातियों के विकास के लिए योजनाओं का संचालन तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार जनजातियों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने सभी लोगों से जनजातियों के संरक्षण-संवर्धन के साथ विकास में सहभागी बनने की अपील की।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार के जनजातीय है इनकी विभिन्न उप जातियां भी हैं। राज्य की आबादी के 31 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। वहीं यदि हम भारतवर्ष की बात करे तो लगभग 10 करोड़ के आबादी जनजातियों की है। छत्तीसगढ़ शासन जनजातियों की समृद्ध विरासत कला, संस्कृति, परंपरा को सहेजते हुए उनके विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्री बोरा बताया कि जनजातीय समाज मुख्य रूप से जल-जंगल, जमीन की बात करते हैं उनकी पूजा अराधना करते हैं, प्रकृति में ही लौकिक-और-अलौकिक शक्ति मानकर अपनी संस्कृति और परंपरा में उसे शामिल भी करते है।

हालांकि आधुनिकता के दौर में संस्कृति और परंपराओं को बचाये रखना चुनौती है। उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य विद्यालय के माध्यम से जनजातियों के मूलभूत सुविधाओं सहित उन क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है।

36.37 करोड़ के 12 कार्यों का भूमिपूजन, 37.45 करोड़ के 7 विकास कार्यों का लोकार्पण

सत्ता शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए : अरुण साव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज कोरबा में सुनालिया नहर मार्ग स्थित बहुप्रतीक्षित मल्टी-लेवल पार्किंग का लोकार्पण तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर का भूमिपूजन किया। उन्होंने नगर निगम द्वारा दादरखुर्द में आयोजित लोकार्पण, भूमिपूजन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर कोरबा जिले को 73 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी।

उन्होंने 36 करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपये की लागत के 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा 37 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपये की लागत के 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वाणिज्य एवं उद्योग लखनलाल देवांगन, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कँवर, महापौर संजू देवी राजपूत और नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, दादरखुर्द में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। गरीबों के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज कोरबा को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है, ऊर्जाधानी कोरबा निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

श्री साव ने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। शासन का प्रत्येक रुपया जनता के हित और विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का भी अब बेहतर एवं जनहितकारी उपयोग हो रहा है। हमारी सरकार शासन करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए है और जनता की यह सेवा निरंतर जारी रहेगी।

उप मुख्यमंत्री ने मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बीते ढाई वर्षों में जिले में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (एएचपी) के हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि आज केवल आवास की चाबी ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में नई खुशियों का भी प्रवेश हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में यहां सड़क, आंगनबाड़ी सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री के मार्गदर्शन में जिले के विकास के लिए लगातार राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में जिले में लगभग एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। इनमें से कुछ पूर्ण भी हो गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए किसानों, गरीबों एवं आम नागरिकों को लाभान्वित किया है। महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

'इन विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन'

उप मुख्यमंत्री साव ने जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, उनमें दर्री बराज-कोहड़िया मार्ग स्थित बेलगरी नाला पर 9 करोड़ 11 लाख 68 हजार रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, कुदमुरा-श्यांग मार्ग के गुरमा नाला पर 5 करोड़ 5 लाख 62 हजार रुपये, लेमरू-श्यांग मार्ग के लमटी नाला पर 3 करोड़ 74 लाख 34 हजार रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, नगर निगम क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु 90 लाख 96 हजार रुपये की लागत से दुकान निर्माण, बालको मार्ग से दर्री मुख्य मार्ग तक 4 करोड़ 45 लाख 11 हजार रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण, वार्ड क्रमांक 31 में विभिन्न नाली एवं कलवर्ट निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 25 शिवाजीनगर, वार्ड क्रमांक 49 प्रगतिनगर तथा वार्ड क्रमांक 52 अयोध्यापुरी में 1500 किलोलीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन, बाउंड्रीवॉल एवं स्विच-रूम निर्माण, आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुदमुरा में आदिवासी कन्या आश्रम, कोरबा में प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कटघोरा में पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य शामिल हैं।

जशपुर वनमण्डल की गजरथ यात्रा-2026 शुरू, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान तेज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जशपुर वनमण्डल की गजरथ यात्रा-2026 शुरू, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान तेजमानव-हाथी द्वंद की घटनाओं में कमी लाने और आमजन, विशेषकर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों में हाथियों के प्रति वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से जशपुर वनमण्डल द्वारा गजरथ यात्रा-2026 का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान हाथी प्रभावित संवेदनशील (येलो ज़ोन) क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है, जहां वन विभाग की टीमें विद्यालयों और गांवों में पहुंचकर हाथियों के व्यवहार, उनके प्राकृतिक आवास तथा सुरक्षित सहअस्तित्व के संबंध में जानकारी दे रही हैं। वन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में आयोजित गजरथ यात्रा के दौरान वन परिक्षेत्र तपकरा के 15 विद्यालयों के 1,542 विद्यार्थियों को हाथियों की जैविक एवं व्यवहारिक विशेषताओं, उनके प्राकृतिक आवास, भ्रमण मार्ग, भोजन एवं जल स्त्रोत, झुंड की संरचना तथा मानव-हाथी सहअस्तित्व से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी दी गई थी। विद्यार्थियों को हाथियों के विचरण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित व्यवहार और वन विभाग की चेतावनियों का पालन करने का प्रशिक्षण भी दिया गया था।

इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए। स्थानीय नागरिकों और विद्यार्थियों में हाथियों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ी। हाथियों के विचरण की समय पर सूचना साझा करने, अफवाहों से बचने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसी आदतों का विकास हुआ, जिससे मानव-हाथी द्वंद की घटनाओं में कमी लाने में मदद मिली।

आधार पर इस वर्ष गजरथ यात्रा-2026 का विस्तार किया गया है। यात्रा जशपुर वनमण्डल के विभिन्न हाथी प्रभावित वन परिक्षेत्रों एवं गांवों में पहुंचकर विद्यालयों, ग्राम सभाओं, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीणों को हाथियों के व्यवहार तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही है।

सेवा सेतु केन्द्र की मदद से बच्चों का जाति प्रमाण पत्र हुआ सहजता से प्राप्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जिला मुख्यालय खैरागढ़ के तुरकारी पारा, निवासी निरंजन सारथी अपने बच्चों सारांश सारथी एवं शिवांश सारथी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते थे। सरकारी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सीमित होने के कारण उन्हें आवेदन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सेवा सेतु केन्द्र, खैरागढ़ से संपर्क किया। केन्द्र के कर्मचारियों ने उन्हें आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी, आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया तथा ऑनलाइन आवेदन तैयार कर जमा कराया। साथ ही आवेदन की नियमित मॉनिटरिंग एवं आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारु और समयबद्ध तरीके से संपन्न हुई।

सेवा सेतु केन्द्र के सहयोग से सारांश सारथी एवं शिवांश सारथी दोनों का जाति प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त हो गया। इससे परिवार को विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्ति, विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज समय पर उपलब्ध हो सके।

श्री निरंजन सारथी ने सेवा सेतु केन्द्र, खैरागढ़ की त्वरित, पारदर्शी एवं जनहितकारी सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि केन्द्र ने पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया। उन्होंने अन्य नागरिकों से भी शासकीय सेवाओं का लाभ लेने हेतु सेवा सेतु केन्द्र की सेवाओं का उपयोग करने की अपील की।

सूरज की रोशनी से जगमगाए घर, महिलाओं की जिंदगी भी हुई रोशन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कबीरधाम जिले की ग्रामीण महिलाओं ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसने उन्हें प्रदेशभर में नई पहचान दिलाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़ी 40 महिलाएं पहली बार 'सोलर दीदी' बनकर न केवल ग्रामीण घरों को रोशन कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की नई मिसाल भी गढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना को जिला पंचायत कबीरधाम ने प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा। जिला पंचायत, बिहान और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के सहयोग से कवर्धा के वंदे मातरम संकुल संगठन को सोलर वेंडर के रूप में पंजीकृत किया गया। टाटा कंपनी ने संगठन की 35 महिलाओं को सोलर पैनल स्थापना और तकनीकी कार्यों का विशेष प्रशिक्षण दिया।

अभियान के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जिले में लगभग 40 घरों में सोलर पैनल लगाने के आदेश मिल चुके हैं। इनमें ग्राम समनापुर की श्रीमती अंजनी पटेल के घर 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया गया है। इसकी लागत 1.80 लाख रुपये है, जिसमें 1.20 लाख रुपये का ऋण संकुल के माध्यम से तथा शेष राशि हितग्राही द्वारा वहन की गई।

पीएम सूर्य घर के तहत स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को छह प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर गोपाल वर्मा के अनुसार, प्रशिक्षित महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं खुली हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को भी इस पहल से जोड़ने की तैयारी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में तीन और महिलाओं के यहां सोलर पैनल स्थापना का कार्य जारी है।

कभी रोजगार की तलाश में रहने वाली ये महिलाएं आज तकनीकी दक्षता के साथ पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। 'सोलर दीदी' के रूप में उनकी यह सफलता ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और हरित ऊर्जाकृतीनों को नई दिशा दे रही है।

अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का दिलाया भरोसा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरसंभव सहयोग का आश्वासन

माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम बनेगा जनसेवा का नया केंद्र : ओपी चौधरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सक्ती जिले के चंद्रपुर स्थित चन्द्रहासिनी विद्यापीठ परिसर में माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम का विधिवत भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि यह बहुउद्देशीय चिकित्सालय क्षेत्रवासियों को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आने वाले समय में जनसेवा का सशक्त केंद्र बनेगा।

मंत्री चौधरी ने कहा कि श्री गोपाल जी महाप्रभु एवं माँ चन्द्रहासिनी देवी मंदिर सार्वजनिक न्यास द्वारा शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट के माध्यम से संचालित सीबीएसई विद्यालय ने क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है और अब आरोग्य धाम की स्थापना समाजसेवा के इस अभियान को नई ऊँचाई देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि चंद्रपुर माँ चन्द्रहासिनी शक्तिपीठ के कारण पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस पवित्र भूमि से उनका वर्षों पुराना आत्मीय संबंध रहा है और प्रशासनिक सेवा के दौरान भी उन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अस्पताल, विद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े किसी भी विकास कार्य में यदि शासन अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई औपचारिक बाधा आती है तो राज्य सरकार हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े ऐसे कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री चौधरी ने कहा कि अस्पताल प्रारंभ होते ही उसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी कराई जाएगी, ताकि आसपास के ग्रामीण आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नि:शुल्क एवं बेहतर उपचार का लाभ प्राप्त कर सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल के विकास और आवश्यक सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने चन्द्रहासिनी महोत्सव को व्यापक पहचान दिलाने के लिए भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। साथ ही विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की यूपीएससी कोचिंग सहायता योजना की जानकारी दी और युवाओं से इसका अधिकाधिक लाभ उठाकर अपने भविष्य को संवारने का आह्वान किया। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि समाज और शासन के साझा प्रयासों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि माँ चन्द्रहासिनी आरोग्य धाम आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं, सेवा भाव और जनकल्याण का आदर्श केंद्र बनेगा।

इस अवसर पर चन्द्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट, चंद्रपुर के संरक्षक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक रामकुमार यादव, ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव सहित जनप्रतिनिधिगण, ट्रस्ट के पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बैंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131

अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

विजय की 'जन नायकन' देखने पहुंचीं तृषा कृष्णन, थिएटर में देखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो

विजय अभिनीत फिल्म 'जन नायकन' गुरुवार को सिनेमाघरों में सज गई है। अभिनेता की रूमर्ड गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी फिल्म देखने पहुंचीं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। बीते दिन शाम से ही दर्शक फिल्म के स्वागत में जश्न मनाने लगे थे। 23 जुलाई को फिल्म रिलीज होते ही बड़ी संख्या में दर्शक इसे देखने सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री तृषा कृष्णन भी 'जन नायकन' देखने सिनेमाघर पहुंची हैं।

थिएटर के बाहर नजर आईं तृषा

अभिनेत्री तृषा कृष्णन गुरुवार को चेन्नई के रोहिणी थिएटर में 'जन नायकन' देखने के लिए पहुंचीं। थिएटर जाते हुए एक्ट्रेस को स्पॉट किया गया। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तृषा वेस्टर्न लुक में खूबसूरत नजर आ रही हैं।

करीब सात महीने की देरी से रिलीज हुई 'जन नायकन'

एच विनोद के निर्देशन में बनी फिल्म 'जन नायकन' थलापति विजय की आखिरी फिल्म है, क्योंकि अब वे पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। इस फिल्म को इसकी मूल रिलीज डेट से करीब सात महीने बाद रिलीज किया गया है। दरअसल, सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिलने के चलते फिल्म की रिलीज अटकी रही। इस बीच फिल्म ऑनलाइन लीक भी हो गई थी। लंबे इंतजार के बाद आखिर दर्शक इसे सिनेमाघरों में देख पा रहे हैं।

फिल्म की स्टारकास्ट

'जन नायकन' में विजय के अलावा पूजा हेगड़े हैं। साथ ही बॉबी देओल और प्रकाश राज जैसे सितारे भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय को इस फिल्म के लिए करीब 220 करोड़ से 275 करोड़ रुपये फीस दी गई है। अगर रिपोर्ट्स में दिए गए फीस के आंकड़ों पर भरोसा करें तो विजय भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं।

विजय का सिग्नेचर स्टाइल देख चिल्लाए फैंस

फिल्म 'जन नायकन' पर अधिकांश नेटिजंस ने सकारात्मक रुख दिखाया है। विजय के हाथ हिलाने वाले सिग्नेचर स्टाइल ने तो मानो महफिल ही लूट ली है। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप वायरल हो रही हैं, जिनमें स्क्रीन पर वह सीन आते ही दर्शक सिनेमाघरों में दीवानों कि तरह चिल्ला रहे हैं।

थलापति ने आग लगा दी

फिल्म में विजय का धमाकेदार डांस भी देखने को मिला है। एक यूजर ने सिनेमाहॉल से क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, 'थलापति ने आग लगा दी'। स्क्रीन पर जब विजय डांस करते दिखे, तो सिनेमाघरों में उनके फैंस भी झूमने लगे।

रात में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना बिगड़ सकती है सेहत और नींद

अगर आप नहीं चाहते कि आपका स्वास्थ्य खराब हो तो अपनी डाइट को थोड़ा बदलें। यहां हम आपको बताएंगे कि रात में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दिनभर की भागदौड़ के बाद रात का खाना शरीर को आराम और पोषण देने का काम करता है। लेकिन अगर इस समय गलत चीजों का सेवन किया जाए, तो इसका असर सिर्फपाचन तंत्र ही नहीं बल्कि नींद, वजन और संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रात का भोजन हल्का, संतुलित और आसानी से पचने वाला होना चाहिए, ताकि शरीर को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और अच्छी नींद मिल सके।

अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और सुबह तरोताजा महसूस करना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि रात के समय किन खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए और उनकी जगह क्या खाना बेहतर विकल्प हो सकता है।

रात में खाने की अच्छी आदतें

- रात का खाना समय पर खाएं।
- सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर करें।
- भोजन अच्छी तरह चबाकर खाएं।
- खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें।
- पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी न पिएं।

रात में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

1. तला-भुना भोजन

समोसा, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज और अन्य तली हुई चीजों में फैट अधिक होता है, जो देर से पचता है। इससे गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

बेहतर विकल्प

हल्की सब्जियां, दाल और मल्टीग्रेन रोटी।

2. ज्यादा मसालेदार खाना

बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन पेट में जलन और एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ा सकता है। इससे रात की नींद भी प्रभावित हो सकती है।

बेहतर विकल्प

कम मसाले वाला घर का बना भोजन।

3. मिठाइयां और शक्कर वाली चीजें

रात में ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और अतिरिक्त कैलोरी वजन बढ़ाने में योगदान दे सकती है।

बेहतर विकल्प

अगर मीठा खाने की इच्छा हो तो सीमित मात्रा में फल खाएं।

4. कैफीन युक्त पेय

रात में चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक पीने से नींद आने में परेशानी हो सकती है। कैफीन कई घंटों तक शरीर में सक्रिय रह सकता है।

बेहतर विकल्प

गुनगुना दूध या हर्बल टी।

5. सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स

इनमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है और गैस की समस्या भी बढ़ सकती है। यह पाचन और नींद दोनों पर असर डाल सकते हैं।

बेहतर विकल्प

सादा पानी या नींबू पानी (बिना ज्यादा चीनी के)।

6. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड

चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड में नमक, प्रिजर्वेटिव और अनहेल्दी फैट अधिक हो सकते हैं।

बेहतर विकल्प

घर का बना ताजा भोजन।

69 साल पुराना दिलीप कुमार का वो गाना, जो बना आंदोलनकारियों की आवाज

रफी साहब ने किया था अमर...

देशभर में फिलहाल छात्र आंदोलन का मामला चर्चा में बना हुआ है। नीट पेपर लीक मामले के विरोध की ये चिंगारी अब और तेज हो गई है। जब कोई शांतिपूर्वक आंदोलन होता है तो उसमें प्रदर्शनकारी कुछ ऐसे फिल्मी गानों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनमें जोश भरते हैं।

इस मामले में हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर रहे दिलीप कुमार का एक 69 साल पुराना सॉन्ग करीब 7 दशकों से पहली पसंद बना हुआ है। इस गीत को दिग्गज गायक रहे मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी।

दिलीप कुमार का यादगार गाना

कहा जाता है कि फिल्मी गानों को निर्माण अक्सर निजी जिंदगी, समाज की समस्या और सुख-दुख के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि अगर हमें देशभक्ति का भावना दिखानी हो तो जहन में देशभक्ति के गीत उमड़ेंगे और अगर मोटिवेशन चाहिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट आसानी से मिलती है।

ठीक इसी प्रकार संगीत के इतिहास में आंदोलनकारियों को लेकर भी गाने बनाए गए हैं, जिनमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला की फिल्म नया दौर (नया दौर - 1957) का पुराना गाना साथी हाथ बढ़ाना...जरूर शामिल होता हैं।

हालांकि, फिल्म के आधार पर इस गीत का संदर्भ उन गरीब गांव वालों से है, जो बिनी किसी तकनीकि सहायता के मजदूर का काम कर एक दूसरे के साथ मिलकर सड़क का निर्माण करते हैं। लेकिन इसका मतलब साफ तौर पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने है।

जो कहीं नहीं किसी भी मसले के खिलाफ सही तौर किए गए विरोध प्रदर्शन को जहन में रखते हुए एक प्रोटेस्ट सॉन्ग का काम करता है। नया दौर के साथी हाथ बढ़ाना... गाने को गायक मोहम्मद रफी के साथ-साथ आशा भोंसले ने भी गया था।

69 साल पुराने गाने को बोल असरदार

दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर को 69 साल पहले रिलीज किया गया था और इस मूवी के गाने साथी हाथ बढ़ाना... के लिरिक्स को साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया था, जो रगो में जोश भरने का काम करते हैं। इस सॉन्ग के संगीतर दिग्गज म्यूजिशियन ओ पी नैय्यर थे।

साथी हाथ बढ़ाना........

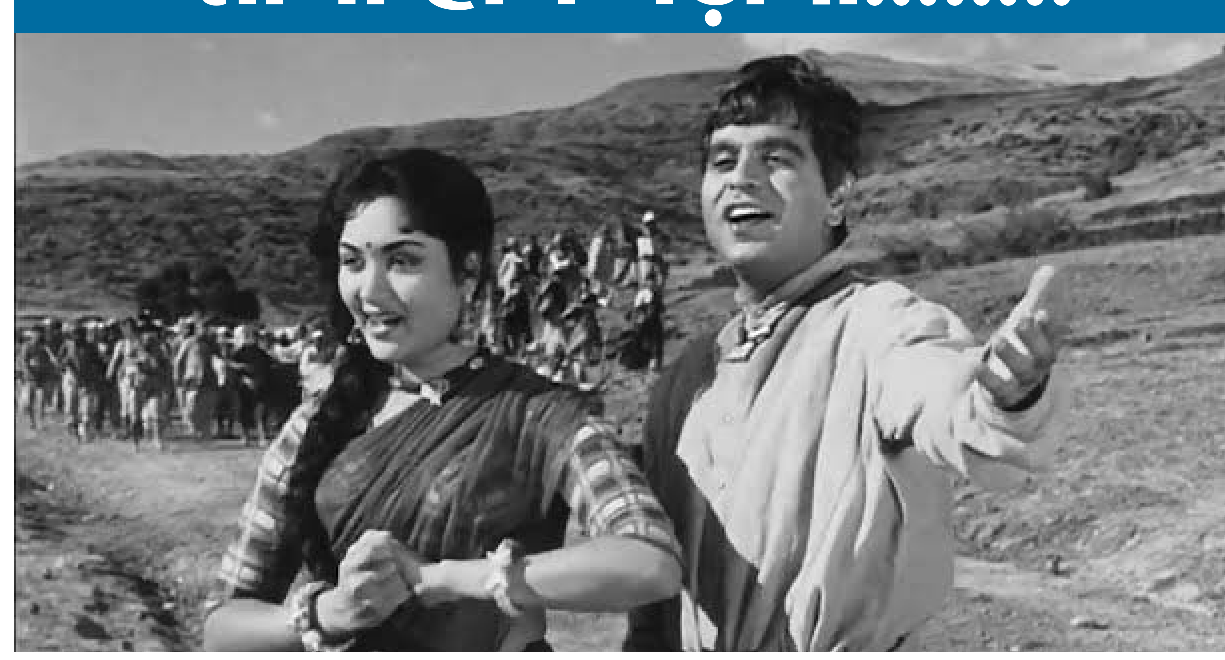

'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद अहान शेट्टी के हाथ लगा जैकपॉट, हॉरर फ्रेंचाइजी में आएंगे नजर

अहान शेट्टी 'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म में नजर आएंगे। अहान के हाथों एक नई फिल्म लगी है। एक्टर इस मूवी में लीग से हटकर एकदम एक नया रोल निभाते नजर आएंगे।

अहान अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सेलेक्टिव हैं और अब जानकारी मिली है कि वो बहुत जल्द एक हॉरर फिल्म में नजर आने वाले हैं।

फिल्म के स्क्रीनप्ले पर हो रहा काम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहान विक्रम भट्ट की पॉपुलर फ्रेंचाइजी 1920 की छठवीं किस्त में नजर आने वाले हैं। इसका नाम 1920: कोल्ड विंटर है। हालांकि फिल्म अभी अपनी राइटिंग स्टेज पर है और विक्रम भट्ट और प्रोड्यूसर आनंद पंडित इसके स्क्रीनप्ले पर काम कर रहे हैं।

मिड-डे को एक सोर्स ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अहान शेट्टी का सुपरनैचुरल जॉनर में पहला काम है। इससे पहले वो साल 2021 में आई रोमांटिक एक्शन-ड्रामा 'तड़प' में काम कर चुके हैं। तड़प उनकी डेब्यू फिल्म भी थी।

कब शुरू होगी शूटिंग

फिलहाल मेकर्स उनके अपोजिट एक फीमेल लीड को कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं। वे इस रोल के लिए किसी न्यूकमर को कास्ट करने के बजाए एक जानी-मानी एक्ट्रेस को लेना चाहते है। अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू हो जाएगी।

फिल्म के कुछ सीन्स स्कॉटलैंड और कुछ शिमला में शूट होंगे। हॉरर जॉनर में कदम रखने से पहले, अहान अब डायरेक्टर टीनू देसाई की फिल्म 'सनकी' में नजर आएंगे। '1920: कोल्ड विंटर' के साथ, यह एक्टर अपनी फिल्मोग्राफी में एक नया आयाम जोड़ सकते हैं।

'हर हफ्ते 50 लाख कमाता हूं', कुशाल टंडन के दावे पर वृद्धि पटवा का बड़ा खुलासा

रियलिटी शो Alliance से हाल ही में बाहर हुई कंटेस्टेंट वृद्धि पटवा ने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई चर्चा छेड़ दी है। वृद्धि ने कहा कि शो के दौरान एक्टर कुशाल टंडन अक्सर अपनी फीस का जिक्र करते थे और दावा करते थे कि उन्हें हर हफ्ते लाखों रुपये मिल रहे हैं। हालांकि, वृद्धि ने ये भी साफ किया कि मीडिया में सामने आई रिपोर्ट्स और कुशाल की बातों में काफी अंतर नजर आया, इसलिए उन्हें खुद भी इस पर हैरानी हुई।

बॉलीवुड बबल टेली को दिए इंटरव्यू में वृद्धि पटवा ने बताया कि शो के दौरान कुशाल टंडन कई बार अपनी कमाई को लेकर बातें करते थे। उनके मुताबिक, कुशाल कहते थे कि उन्हें शो में हिस्सा लेने के लिए हर सप्ताह करीब 50 लाख रुपये मिल रहे हैं। वृद्धि ने कहा कि जब बाद में उन्होंने खबरें पढ़ीं, जिनमें पूरे सीजन की फीस लगभग 1 करोड़ रुपये बताई गई थी, तो वो खुद कन्फ्यूज हो गईं। इतना ही नहीं, वृद्धि ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने एक बार मजाक में कुशाल से ये भी कह दिया था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 50 लाख रुपये कमाते हैं या 5 लाख रुपये। उनके मुताबिक, किसी कंटेस्टेंट की कमाई से ज्यादा जरूरी खेल और प्रदर्शन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छी रकम कमा रहा है तो उसे बार-बार उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

कुशाल टंडन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई

इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कुशाल टंडन की ओर से अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए वृद्धि के बयान को फिलहाल उनके व्यक्तिगत दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो वहीं, शो की बात करें तो हालिया एपिसोड में 'हंटर्स' टीम सबसे नीचे रही, जिसके बाद टीम के सभी सदस्य एलिमिनेशन के खतरे में आ गए। सिस्टम द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक, जो खिलाड़ी दिन का टास्क पूरा नहीं कर पाया, उसे तुरंत शो छोड़ना पड़ा। इसी चुनौती में वृद्धि पटवा सफल नहीं हो सकीं और उनका सफर यहीं समाप्त हो गया।

बता दें, वृद्धि के बाहर होने के बाद अब शो में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है, जिसमें कशिश कपूर का नाम है, जो पहले एमटीवी स्प्लिट्सविला-5 और बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी हैं और अब 'एलायंस' का हिस्सा बनेंगी। उनकी एंट्री से शो में नए समीकरण बनने और पुराने रिश्तों में बदलाव देखने को मिल सकता हैं।

छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगी पहली राजकीय तितली, 31 अगस्त तक आमजन कर सकेंगे मतदान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ अपनी पहली राजकीय तितली चुनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसके लिए प्रदेशवासियों से ऑनलाइन मतदान के माध्यम से सुझाव मांगे हैं। नागरिक अपनी पसंद की तितली के लिए **Google Form** के माध्यम से 31 अगस्त 2026 तक मतदान कर सकते हैं।

वनमंत्री केदार कश्यप की पहल पर शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता और तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से

अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता और वन्यजीवों का संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। जनभागीदारी से राजकीय तितली का चयन होने से लोगों में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राजकीय तितली के चयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने वैज्ञानिक और पारिस्थितिक मानकों के आधार पर तीन तितली प्रजातियों का चयन किया है। इनमें कॉमन बैंडेड पीकॉक **(Common Banded Peacock)**, ऑरेंज ओकलीफ **(Orange Oakleaf)** और स्पॉट स्वोर्डटेल **(Spot Swordtail)** शामिल हैं।

इन तितली प्रजातियों का चयन राज्य में उनकी उपलब्धता, पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण मूल्य, विशिष्टता, आसानी से पहचान में आने और आमजन के आकर्षण जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया गया है।

जनमत और विशेषज्ञों की अनुशंसा से होगा अंतिम चयन

वन विभाग द्वारा नागरिकों की राय जानने के लिए ऑनलाइन मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद की तितली के पक्ष में मतदान कर सकता है। प्राप्त जनमत और विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राजकीय तितली के चयन का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

विद्यार्थियों और प्रकृति प्रेमियों से भी भागीदारी की अपील

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश के सभी नागरिकों, विद्यार्थियों, प्रकृति प्रेमियों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। विभाग ने लोगों से अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता के इस महत्वपूर्ण प्रतीक का चयन व्यापक जनभागीदारी से हो सके।

खास-खबर

दुगली वन धन विकास केंद्र ने बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का दुगली वन धन विकास केंद्र आदिवासी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख मॉडल बन चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के मार्गदर्शन में 10 महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से, यह केंद्र ग्रामीण महिलाओं की आय और सामाजिक स्थिति को सशक्त बना रहा है। यह केंद्र पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के माध्यम से लगभग 25 प्रकार के औषधीय और खाद्य उत्पाद तैयार करता है। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा किए हैं। इस योजना से जुड़कर धमतरी जिले के दुगली वन धन विकास केंद्र की महिलाएं अब वनोपज का मूल्य संवर्धन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य औषधीय और खाद्य उत्पाद तैयार कर अपनी आय बढ़ा रही हैं और अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं।

शिल्पनगरी में 40 शिल्पियों को वितरित किए आधुनिक टूल किट

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने गुरुवार को कोंडागांव स्थित शिल्पनगरी का दौरा कर शिल्पकारों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिले के 40 शिल्पियों को आधुनिक टूल किट वितरित किए। इसमें 20 बेलमेटल एवं 20 लौहशिल्प के शिल्पकार शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन स्थानीय कला, संस्कृति और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, संवर्धन तथा शिल्पकारों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव की शिल्पकला जिले की विशिष्ट पहचान है, जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि शिल्पकार अपनी कलाकृतियों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शबरी एम्पोरियम एक माध्यम है। साथ ही आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण लेकर बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करें।

धमतरी बना प्रदेश का पहला जिला, जहां पीएसीएस के जरिए किसानों को मिलेगी ड्रोन स्प्रेयर सेवा

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खुद उड़ाया ड्रोन, जिले की 10 समितियों में आधुनिक कृषि तकनीक का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों को वैज्ञानिक खेती की ओर अग्रसर करने की दिशा में धमतरी जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। धमतरी राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। वन, जलवायु परिवर्तन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम लोहरसी स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जिले की 10 चुनिंदा समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री श्री कश्यप ने स्वयं ड्रोन उड़ाकर उसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया और किसानों को खेती में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं ने ड्रोन स्प्रेयर का सफल प्रदर्शन किया। कृषि विशेषज्ञों और किसानों को दिखाया गया कि कैसे यह तकनीक कम समय में

अधिक क्षेत्रफल में उर्वरकों और कीटनाशकों का बिल्कुल सटीक छिड़काव कर सकती है।

इस अवसर मंत्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। सहकारी समितियों के जरिए गाँव-गाँव तक ड्रोन पहुँचाना खेती को अधिक लाभकारी, सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाएगा। धमतरी को कृषि नवाचारों का मॉडल जिला बनाया जा रहा है और जल्द ही इस सुविधा का विस्तार राज्य की अन्य समितियों में भी किया जाएगा। धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि प्रथम चरण में जिले की 10 समितियों को इस सुविधा से जोड़ा गया है। जिसमें बोड़रा, लोहरसी, दोनर, अछोटा, खरेंगा, भोथीडीह, कुंडेल,गाड़ाडीह, जुगदेही और करेली शामिल है। इन समितियों के माध्यम से किसान नाममात्र के सेवा शुल्क पर अपने खेतों के लिए ड्रोन छिड़काव सेवाएँ बुक कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने समिति परिसर में नवनिर्मित कृषि एवं कीटनाशक विक्रय केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए।

मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगी समितियाँ

यह पहल केवल कृषि तक सीमित नहीं है। **CSC e-Governance Services India Limited** के सहयोग से इन **PACS** को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इससे किसानों को खेती-किसानी के साथ-साथ विभिन्न डिजिटल और शासकीय सेवाएँ भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

पर्यावरण सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार

ड्रोन तकनीक से फसलों पर रसायनों का संतुलित और लक्षित उपयोग संभव होगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम पहुँचेगा और फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी। साथ ही, ड्रोन संचालन और रखरखाव से ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए द्वार खुलेंगे।

प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना लक्ष्य- मुख्य सचिव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर नल (जल जीवन मिशन) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना से महिलाओं का समय बचेगा और जलजनित बीमारियों में कमी आएगी तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में मिशन मोड में कार्य करते हुए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि वे प्रत्येक माह जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करें। बैठक में मुख्य सचिव ने पूर्ण हो चुकी और हस्तांतरित योजनाओं के भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका 31 अगस्त तक भौतिक सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन योजनाओं का कार्य अधूरा है, उन्हें 31 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टर समयबद्ध तरीके से रनिंग बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य बाधित नही हो।

सेवा सेतु से आसान हुई दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया विद्यार्थियों के भविष्य को मिला नया सहारा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल पर संचालित सेवा सेतु पोर्टल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। इस पहल के माध्यम से नागरिकों को आवश्यक शासकीय दस्तावेज सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया से उपलब्ध हो रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों का समय, श्रम और आर्थिक खर्च बच रहा है।

बड़े बचेली के कोआपारा निवासी राजू कुंजाम ने अपने पुत्र रेवांथ कुंजाम का निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र की आगे की पढ़ाई और विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक था। श्री कुंजाम ने बताया कि पहले ऐसे दस्तावेज बनवाने के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन सेवा सेतु के माध्यम से उनका आवेदन आसानी से स्वीकार किया गया और समय पर निवासी प्रमाण पत्र मिल गया। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र मिलने से उनके पुत्र की शिक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सुविधा हुई है। इसी तरह ग्राम मल्लेमुंडा, ग्राम पंचायत मुचनार निवासी श्री संतुराम वेक ने अपने पुत्र सुभाष वेक का आय प्रमाण पत्र सेवा सेतु के माध्यम से बनवाया। आवश्यकता शैक्षणिक कार्यों और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए थी। सेवा सेतु अभियान के माध्यम से उन्हें बिना किसी अनावश्यक परेशानी के आवश्यक प्रमाण पत्र मिल गया। श्री वेक ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण परिवारों को दस्तावेज बनवाने में काफी सुविधा मिल रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले के अनेक ग्रामीण परिवारों को विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।

महुआ के अचार और शहद से बदल रही ग्रामीण महिलाओं की तकदीर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से प्रदेशभर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार सफल हो रहे हैं।

इसका प्रेरक उदाहरण मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम रामगढ़ में देखने को मिला है, जहां माँ रामेश्वरी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने महुआ के अचार और शहद निर्माण

को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनाई है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से समय पर मिली वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के बल पर समूह की महिलाएं आज सफल उद्यमी बन चुकी हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि स्थानीय वनोपज का वैज्ञानिक उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार और आय के स्थायी अवसर विकसित किए जा सकते हैं। कभी आर्थिक तंगी और घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली समूह की 10 महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से अपनी आजीविका को नई दिशा दी। पिछले एक वर्ष से वे महुआ का अचार और शहद तैयार कर बाजार में विक्रय कर रही हैं। इस दौरान समूह ने अपने उत्पादों से लगभग एक लाख रुपये की आय अर्जित की है। इस अतिरिक्त आय ने न केवल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास और उद्यमिता की भावना को भी बढ़ावा दिया है। समूह की सदस्य श्रीमती सुशीला कुरेटी बताती हैं कि पहले घरेलू आवश्यकताओं और छोटे-छोटे खर्चों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज वे आत्मनिर्भर हैं। अब वे अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा, परिवार की जरूरतों की पूर्ति और घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनका कहना है कि बिहान योजना ने उन्हें केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और समाज में नई पहचान भी दी है।

बाल श्रम पर जीरो टॉलरेंस, हर मुक्त बच्चे के पुनर्वास पर होगा विशेष फोकस

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की समीक्षा बैठक में बहुस्तरीय कानूनी कार्रवाई और समयबद्ध पुनर्वास के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की अध्यक्षता में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बाल श्रमिकों के त्वरित रेस्क्यू, प्रभावी कानूनी कार्रवाई, विभागीय समन्वय तथा समग्र पुनर्वास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रेस्क्यू किए गए प्रत्येक बाल श्रमिक को अनिवार्य रूप से बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उनके संरक्षण, देखरेख और पुनर्वास की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी मुक्त बच्चे को केवल बचाव तक सीमित न रखते हुए उसे शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और सम्मानजनक जीवन से जोड़ना सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी है।

समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कई मामलों में बाल श्रमिकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता एवं क्षतिपूर्ति के वितरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग अध्यक्ष ने पात्र बच्चों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उनके पुनर्वास में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि बाल श्रम के मामलों में कार्रवाई केवल बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रकरण की प्रकृति के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, किशोर न्याय अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत भी तत्काल एफआईआर दर्ज कर प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाएगा। दोषी नियोजकों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई तथा मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास संबंधी सभी वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में प्रत्येक जिले की बाल श्रम टास्क फोर्स और बंधुआ मजदूरों के लिए गठित सतर्कता समिति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करने पर सहमति बनी। साथ ही गृह, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा कौशल विकास विभाग की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

आयोग ने सभी जिलों में श्रम अधिकारियों एवं श्रम निरीक्षकों के लिए बाल श्रम उन्मूलन, विधिक कार्रवाई और पुनर्वास संबंधी विशेष प्रशिक्षण एवं नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने तथा उनकी अनुपालन रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल श्रम के प्रति शजीरो टॉलरेंसश् की नीति पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे का बचपन श्रम की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। बाल श्रम कराने वाले प्रत्येक दोषी के विरुद्ध कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रत्येक मुक्त बच्चे को सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक भविष्य उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग समन्वित एवं संवेदनशील तरीके से कार्य करेंगे।

नैनो यूरिया के उपयोग से किसान दिगपाल को मिला बेहतर उत्पादन

रायपुर। कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसान न केवल उत्पादन बढ़ा रहे हैं, बल्कि लागत भी कम कर रहे हैं। जिला सक्ती के विकासखंड सक्ती अंतर्गत ग्राम डोड़की निवासी किसान श्री दिगपाल सिंह चौहान नैनो यूरिया का उपयोग कर क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं द्य श्री चौहान पिछले वर्ष से अपनी लगभग 10 एकड़ धान की फसल में कृषि विभाग के मार्गदर्शन में नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। दिगपाल ने बताया कि शुरू में नैनो यूरिया को लेकर जिज्ञासा थी, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहे। इसके उपयोग से धान की फसल की वृद्धि बेहतर हुई, पौधे अधिक हरे-भरे और स्वस्थ रहे तथा उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 100 टन चावल की हेराफेरी, संचालक गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेक्टर-7 स्थित एक सरकारी राशन की दुकान से 100 टन से भी ज्यादा चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने अनियमितताओं की शिकायत पर जब जांच की तो स्टॉक में 1007.51 क्विंटल चावल कम पाया गया। इस मामले में खाद्या विभाग की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर राशन दुकान के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल 22 जुलाई 2026 को कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला दुर्ग के आदेश के परिपालन में खाद्य निरीक्षक द्वारा थाना भिलाई नगर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान, सेक्टर-07 मार्केट, भिलाई (दुकान आईडी-431004118) के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत एवं विक्रेता नमिता सिन्हा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई एफआईआर दर्ज कराई गई।

पुलिस को दिए गए शिकायत के आधार पर कलेक्टर, जिला दुर्ग के आदेशानुसार गठित जांच समिति द्वारा ने संबंधित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान के अभिलेखों, उपलब्ध स्टॉक एवं ऑनलाइन प्रदर्शित खाद्यान्न की मात्रा का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी एवं बारदाना पंजी उपलब्ध पाए गए, जबकि स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि स्टॉक पंजी विक्रेता के पास है।

भौतिक सत्यापन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड के मिलान में 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। जांच के समय दुकान में केवल 26.50 क्विंटल चावल उपलब्ध था, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 1034.01 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, किन्तु संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर पंचनामा तैयार कर कथन दर्ज किए गए।

प्रारंभिक जांच में संबंधित संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 5, 11, 12, 13, 14 एवं 15 तथा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जो कंडिका 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है। खाद्य विभाग की शिकायत पर थाना भिलाई नगर में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान दस्तावेजों के परीक्षण, साक्ष्य संकलन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई उपरांत आरोपी संचालकनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में थाना भिलाई नगर पुलिस एवं खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत खाद्य निरीक्षक, विवेचना अधिकारी एवं थाना स्टाफ द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी, अनियमित वितरण अथवा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा खाद्य विभाग को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

खास खबर

खुले प्लॉट में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

रायपुर। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में डुंडा स्थित स्वागत विहार कॉलोनी के एक खुले प्लॉट में बुधवार दोपहर महिला का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी और रायपुर पश्चिम जोन के डीसीपी रॉबिनसन गुरिया मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस जांच में मृतका की पहचान सुभद्रा साहू (35 वर्ष) के रूप में हुई है। वह बोरियाकला की रहने वाली थी और घरों में काम कर परिवार का भरण-पोषण करती थी। बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह काम पर निकली थी, लेकिन कुछ देर बाद उसका शव खुले प्लॉट में मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। एफएसएल और डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

व्यापारी से 2.04 करोड़ की ठगी, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। जिले में शेयर मार्केट में निवेश कर रकम दोगुनी करने का लालच देकर एक व्यापारी से 2 करोड़ 4 लाख 97 हजार 502 रुपये की ठगी करने वाले फरार पति-पत्नी को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थे। पुलिस ने नया रायपुर से उन्हें पकड़कर लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन और चेकबुक जब्त किए हैं। चांपा निवासी बैटरी व्यापारी हेमदत्त केशरवानी ने 24 मई को थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पहचान मारुति विहार कॉलोनी निवासी हरिशंकर गुप्ता और उनकी पत्नी रेखा गुप्ता से थी। हरिशंकर ने खुद को यूनियन बैंक चांपा का कर्मचारी बताया और शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने पर रकम दोगुनी होने का भरोसा दिलाया। झांसे में आकर व्यापारी ने बैंक से लोन लेकर तथा अन्य लोगों के माध्यम से चेक और आरटीजीएस के जरिए 2.04 करोड़ रुपये से अधिक उनके खातों में जमा करा दिए। आरोपियों ने केवल 39 लाख 99 हजार 400 रुपये लौटाए और बाकी रकम देने में टालमटोल करते हुए फरार हो गए। पुलिस टीम ने दबिश देकर हरिशंकर गुप्ता (43) और रेखा गुप्ता (42) को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने ठगी की बात स्वीकार कर ली।

सीए ऑफिस में 7.80 लाख की चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालय से 7.80 लाख रुपए चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने वारदात के महज 30 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। चोरी की पूरी साजिश ऑफिस के पूर्व कर्मचारी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रची थी। आरोपियों का नाम उमेश पोर्ते और लक्ष्मीनारायण ध्रुव बताया जा रहा है। चोरी की पूरी 7.80 लाख रुपए कैश बरामद कर ली गई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी उमेश पोर्ते के खिलाफ पहले भी बिलासपुर में मारपीट के मामले दर्ज हैं और वह जेल जा चुका है। बीएनएस की धारा 331(4) और 305 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है।

छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर गांजा तस्करी बीच रास्ते पुलिस ने दो आरोपी को पकड़ा

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। बस्तर पुलिस ने एक बार फिर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस ने ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से 11 किलो 673 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख 84 हजार रुपए है। दोनों आरोपी गांजा को रायपुर ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, 21 जुलाई को सूचना मिली थी कि दो युवक धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास संदिग्ध हालत में बैग लेकर बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ा।

पूछताछ में उन्होंने अपना नाम ललित कुशुलिया और बिरन्ची गोरोडिया बताया, जो ओडिशा के रायगढ़ा जिले के निवासी हैं। पुलिस ने जब दोनों के बैग की तलाशी ली तो उसमें 10 पैकेट में भरा हुआ गांजा मिला।

मौके पर वजन कराने पर कुल 11 किलो 673 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजा की कीमत 5 लाख 83 हजार 650 रुपए बताई गई है। शुरुआती पूछताछ में यह जानकारी मिली कि आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर रायपुर जा रहे थे।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सीएसपी सुमीत कुमार ने कहा कि, जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

12 साल की नाबालिग बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म

बालोद। गुंडरदेही थाना क्षेत्र में एक पिता के द्वारा अपनी ही 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पीड़ित बच्ची अपनी मां के साथ थाने पहुंची और अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बिना देरी किए अपराध दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

जमीन विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से हत्या, कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जमीन विवाद में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पर 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता देने की अनुशंसा की है।

मामला 28 जनवरी 2024 का है। चक्रधरनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम नवापाली मेन रोड पर जमीन समतलीकरण के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने विशाल सिंह ठाकुर के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से कई वार कर उसकी हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में सामने आया कि विशाल सिंह ठाकुर जमीन में मिट्टी डालकर समतलीकरण और झाड़ियों की सफाई करा रहे थे। इसी दौरान हरिलाल खड़िया (30), निवासी माझापारा, बड़े अतरमुड़ा मेडिकल कॉलेज रोड, ने जमीन पाटने को लेकर विवाद किया और कुल्हाड़ी से सिर व गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, खून से सनी टोपी, चश्मा, चप्पल, रक्तरंजित मिट्टी सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए। 29 जनवरी 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े बरामद किए गए। जब्त सामग्री को एफएसएल भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट भी अभियोजन के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य बनी।

मामले में अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। विवेचना अधिकारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य पेश किए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी हरिलाल खड़िया को हत्या का दोषी ठहराया।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर कार्रवाई, रेत के अवैध कारोबार पर कसा शिकंजा

श्रीकंचनपथ न्यूज

मरवाही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में लगातार प्रभावी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण की नीति अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिणाम दे रही है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध रेत भंडारण स्थल को सीलबंद किया तथा अवैध परिवहन में संलिप्त दो ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर सख्त कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप शासन की प्राथमिकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए तथा जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।

मरवाही में अवैध रेत भंडारण स्थल सील, दो ट्रैक्टर वाहन जब्त

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मरवाही के सिवनी चौक स्थित अवैध रेत भंडारण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जांच के उपरांत संबंधित भंडारणकर्ता को 15 जुलाई 2026 को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। निर्धारित अवधि में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 के प्रावधानों के तहत अवैध रेत भंडारण स्थल को मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।

मरवाही एवं पिपरिया क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में संलिप्त दो ट्रैक्टर वाहनों को भी जब्त किया गया। जब्त वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज संबंधी प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है।

जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

इस पूरी कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी आदित्य मानकर, खनिज निरीक्षक सुजीत कंवर, शिवकुमार लहरे, सतीश साहू तथा साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की अवधारणा को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई से न केवल आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लग रहा है। यह पहल पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है।

सिविल सर्जन 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

सक्ती। सक्ती जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. संतोष कुमार पटेल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारी का वेतन संबंधी पे-डेटा सीएमएचओ कार्यालय भेजने के बदले रिश्वत की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रभारी सिविल सर्जन की गिरफ्तारी के बाद सक्ती जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में एसीबी आगे की जांच कर रही है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, बालोद (छ.ग.)

निविदा क्र. 04/ले.शा.(निविदा)/का.अ./लो.स्वा.यां.खण्ड/2026 बालोद, दिनांक : 22-07-2026

ई-प्रॉक्यूरमेंट द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

ऑनलाईन निविदाएं **प्रपत्र-एफ** में लम्प-सम दर पर नीचे उल्लेखित कार्य के लिये कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद द्वारा के एकीकृत पंजीयन व्यवस्था ई-रजिस्ट्रेशन की **सक्षम श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण:-

सिस्टम नं.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	अमानत राशि
195965	डौण्डी	बालोद जिले के विकासखंड डौण्डी के दल्लीराजहरा नगरीय जल प्रदाय योजनांतर्गत 03 नग क्लीयर वाटर सेन्ट्रीफ्यूगल पंप सेट्स प्रदाय तथा स्थापित करने एवं 02 नग 33/0.415 KV 160 KVA आउटडोर ट्रांसफार्मर प्रदाय तथा स्थापना तथा अन्य कार्य (शेड्यूल के अनुसार सम्पूर्ण कार्य सामग्री सहित)	रु. 50.11 लाख	38,000.00

1. **बिड सबमिशन प्रारंभ की तिथि :- 24/07/2026**
2. **बिड सबमिशन की अंतिम तिथि :- 11/08/2026**

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल **http://eproc.cgstate.gov.in** दिनांक 24/07/2026 से एवं कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखे जा सकते है।

जी-262702304/5

कार्यापालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद
जिला - बालोद (छ.ग.)

रायपुर में गौवंश के साथ कथित अनाचार का मामला, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में गौवंश के साथ कथित अनाचार का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उरला थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, सत्य नगर बीरगांव निवासी एवं विश्व हिंदू परिषद बंजारी प्रखंड के सहमंत्री वीरेंद्र विश्वकर्मा ने लिखित शिकायत में बताया कि 21 जुलाई की सुबह उन्हें सूचना मिली कि राजेंद्र नगर उरला निवासी सूरज कुमार ने गौवंश के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक कृत्य किया है। शिकायत में इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायत के अनुसार, बजरंग दल के कार्यकर्ता राहुल राजभर ने घटना से जुड़ा एक वीडियो और अन्य जानकारी साझा की थी। दावा किया गया है कि यह घटना 20 और 21 जुलाई की दरम्यानी रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हुई। वीडियो की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर उरला थाने ले गए।

उरला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सूरज कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत अपराध दर्ज किया है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से जुड़े वीडियो, शिकायतकर्ता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हालांकि आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हादसा : ट्रेन शुरू होने के बाद चढ़ने के प्रयास में फिसला यात्री, चपेट में आने से मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन चढ़ने के प्रयास में फिसल कर उसी ट्रेन की चपेट में आने से यात्री की मौत हो गई। गुरूवार सुबह प्लेटफार्म नंबर दो और तीन के बीच जैसे यात्री फिसलकर गिरा तो अफरार तफरी मच गया। ट्रेन निकलने के बाद एंबुलेंस की मदद से घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 6:15 बजे ट्रेन संख्या 22845 पुणे- हटिया एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर तीन पर खड़ी हुई थी। जब ट्रेन चलने लगी तब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक वार्ड नंबर 58 साईं मंदिर के पास कर्मचारी नगर दुर्ग निवासी संदीप कुमार सिन्हा (58) ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान उसका पैर स्लिप हो गया और वह गिरकर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में फंस गये।

ट्रेन उनके एक पैर के ऊपर से गुजर गई जिससे पैर कट गया। गंभीर रूप से घायल संदीप कुमार सिन्हा को तुरंत एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बताया गया कि संदीप कुमार सिन्हा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की रायपुर शाखा में एरिया मैनेजर के पद पर पदस्थ थे और कार्यालयीन कार्य से ट्रेन के माध्यम से रायपुर जा रहे थे। जीआरपी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है।

अमलीपदर की रथयात्रा आस्था और संस्कृति की अमूल्य धरोहर : मुख्यमंत्री

भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। अमलीपदर की ऐतिहासिक रथयात्रा छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान श्री जगन्नाथ सबको साथ लेकर चलने और लोककल्याण का संदेश देते हैं। महाप्रभु का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे, यही उनकी प्रार्थना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गरियाबंद जिले के अमलीपदर में आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा महापर्व को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए और भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, राजिम विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अंतिम तिथि, जो जून माह तक निर्धारित थी, उसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन माह बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि अंतरित की जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं का सशक्त होना विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत आधारशिला है और राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा वे स्वयं प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 42 हजार से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है, जो सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

बाल्टीजोर नाले पर बनेगा पुल

क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाल्टीजोर नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र के लोगों को वर्षभर सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से किया आत्मीय संवाद

रथयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना काफिला रोककर सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और विद्यालय की गतिविधियों के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके आग्रह पर बच्चों के साथ आत्मीयता से सेल्फी भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री का यह सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार उपस्थित लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की रही सहभागिता

रथयात्रा महापर्व में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठानों, भक्ति संगीत और जयघोषों के बीच पूरा अमलीपदर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। कलेक्टर बी.एस. उईके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान

32 पदकों से चमके खिलाड़ी, सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया उत्साहवर्धन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कोरबा में डीडीएम रोड स्थित सीएमए किकबॉक्सिंग एकेडमी में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं हनुमान चालीसा भेंट कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में सीएमए किकबॉक्सिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल 32 पदक जीतकर कोरबा एवं छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अर्जित करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र ष्जो खेलेगा, वो खिलेगाष् आज देशभर के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में बस्तर ओलंपिक, खेल अलंकरण समारोह, उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरस्कार तथा पहली बार सरगुजा ओलंपिक जैसी पहलें शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में खेलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में शीघ्र ही हॉकी लीग का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना को लगातार सुदृढ़ कर रही है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से देश और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का आह्वान करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतना खिलाड़ियों की प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम का परिचायक है। किकबॉक्सिंग एक चुनौतीपूर्ण खेल है और इसमें सफलता प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास केवल खेल तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़े रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से खिलाड़ियों को हनुमान चालीसा भेंट की गई है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने माता-पिता, जिले और प्रदेश का नाम निरंतर रोशन करने का आह्वान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान महापौर संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह, प्रेस क्लब अध्यक्ष नौशाद खान, जनप्रतिनिधिगण, पार्षद, किकबॉक्सिंग समिति के पदाधिकारी, प्रशिक्षक, खिलाड़ी एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे।

सरस्वती साइकिल योजना से बेटियों के सपनों को मिले पंख

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कभी लंबी दूरी और आवागमन की परेशानी कई ग्रामीण बेटियों की पढ़ाई में बाधा बनती थी। अब वही राह आसान हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना ने बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अचौद की छात्राओं के सपनों को नए पंख दे दिए हैं। इस वर्ष भी योजना के तहत विद्यालय की 32 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं।

शाला प्रबंधन समिति, प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं और अभिभावकों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को साइकिलें सौंपी गईं। यह केवल एक वितरण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ग्रामीण बेटियों की शिक्षा को नई गति देने का संकल्प भी था। अचौद विद्यालय में खुटेरी, फुंडा, बोरगहन और रजोली जैसे आसपास के गांवों से छात्राएं अध्ययन के लिए आती हैं। पहले लंबी दूरी तय करने में काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। अब साइकिल मिलने से उनका सफर सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध हो गया है। इसका सकारात्मक असर उनकी नियमित उपस्थिति, समयपालन और पढ़ाई के प्रति बढ़ते उत्साह में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी बड़ी राहत दी है। अब अभिभावकों को बच्चों के आवागमन के लिए अलग से खर्च या साधन जुटाने की चिंता नहीं रहती। इससे वे अपनी बेटियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं। विद्यालय में वितरित की गई ये साइकिलें केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक हैं। सरस्वती साइकिल योजना यह साबित कर रही है कि जब बेटियों को अवसर और संसाधन मिलते हैं, तो वे अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता स्वयं बना लेती हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950